मार्च – अप्रैल 2009

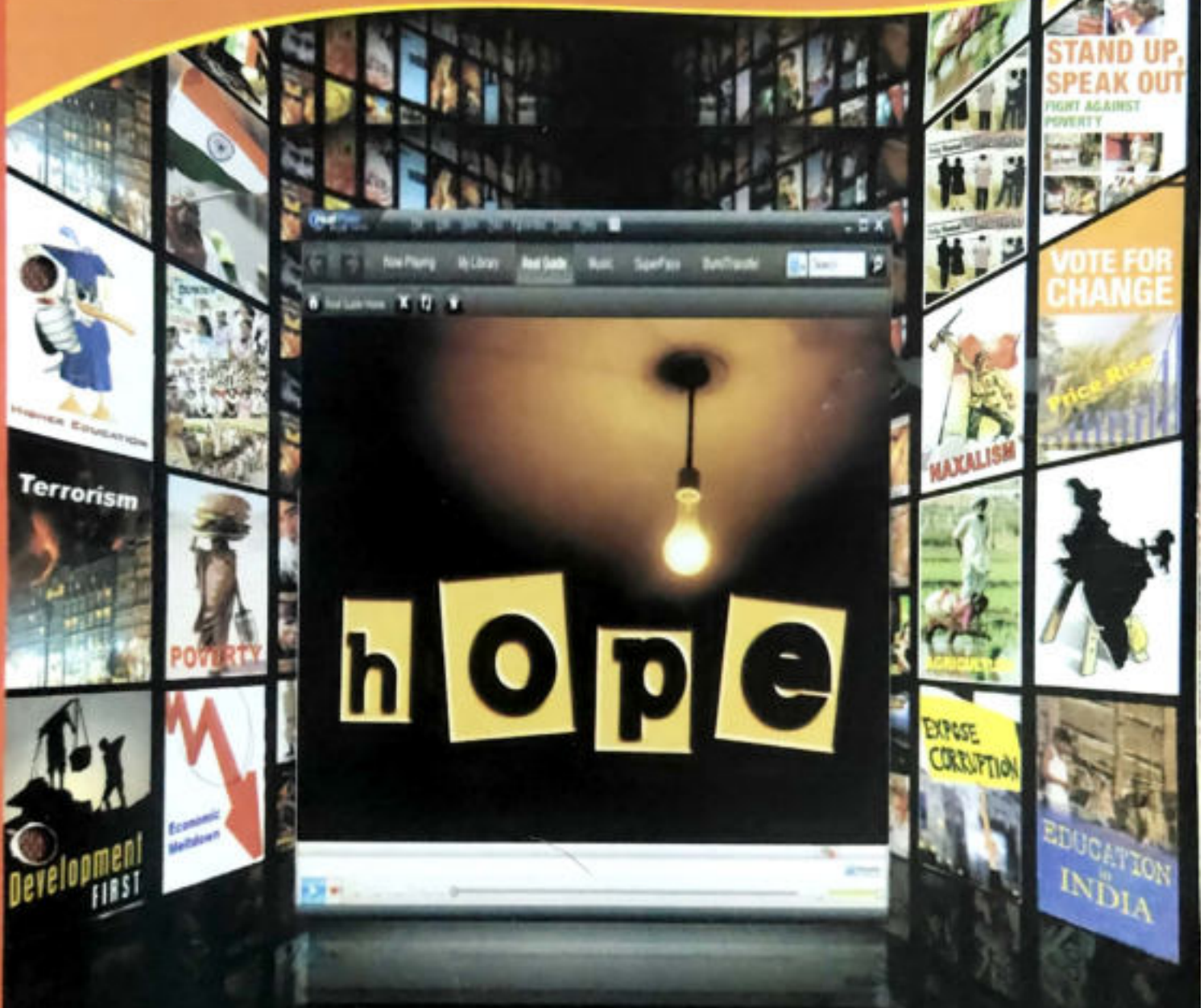

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

चुनाव सम्पन्न
जिम्मेदारी शेष

वर्ष : 32 अंक : 2

युवा मतदाता जागरण अभियान

Campaign

Street Play

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति
शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका
वर्ष : 32 अंक : 2 ● मार्च – अप्रैल 2009

संरक्षक
अतुल कोठारी

संपादक
डा. मुकेश अग्रवाल

प्रबंध संपादक
नितिन शर्मा

संपादक मंडल
संजीव कुमार सिन्हा
आशीष कुमार 'अंशु'
उमाशंकर मिश्र

फोन : 011 – 23093238, 27662477
E-mail : chhathrashakti@gmail.com
Website : www.abvp.org

डा. रंजीत ठाकुर द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बी–50, क्रिश्चियन कॉलोनी, पटेल चेस्ट, दिल्ली–110007 के लिए प्रकाशित एवं पुष्पक प्रेस, 119, डीएसआईडीसी कॉम्प्लेक्स, ओखला, फेज–1, नई दिल्ली–20 द्वारा मुद्रित

विषय सूची

7 समाज के लिए थोड़ा समय दें

9 चुनाव सम्पन्न – जिम्मेदारी शेष

11 उच्च शिक्षा में लोचे बड़े

12 संवैधानिक पदों की गरिमा का सवाल

15 **UGC Norms Equate Ragging With Rape**

18 जरूरी है छद्म–सेक्युलरवादियों से बच कर रहना

21 **Whose elections were these anyway?**

27 **Career**

परिचर्चा

नई सरकार के समक्ष चुनौतियां 25

परिषद् गतिविधियां 29

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण सम्बन्धित लेखकों के हैं। सम्पादक, प्रकाशक, एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली रहेगा।

कविता

कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।

— हरिवंशराय बच्चन

लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।

नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है,
चढ़ती दीवारों पर, सौ बार फिसलती है।
मन का विश्वास रगों में साहस भरता है,
चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है।
आखरि उसकी मेहनत बेकार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।

डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है,
जा जा कर खाली हाथ लौटकर आता है।
मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में,
बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में।
मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।

असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो,
क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो।
जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम,
संघर्ष का मैदान छोड़ कर मत भागो तुम।
कुछ किये बिना ही जय जय कार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।

कदम मिला कर चलना होगा

अटल बिहारी वाजपेयी

बाधाएँ आती हैं आएँ
घिरें प्रलय की घोर घटाएँ,
पावों के नीचे अंगारे,
सिर पर बरसें यदि ज्वालाएँ,
निज हाथों में हँसते–हँसते,
आग लगाकर जलना होगा।
कदम मिलाकर चलना होगा।

हास्य–रूदन में, तूफानों में,
अगर असंख्यक बलिदानों में,
उद्यानों में, वीरानों में,
अपमानों में, सम्मानों में,
उन्नत मस्तक, उभरा सीना,
पीड़ाओं में पलना होगा।
कदम मिलाकर चलना होगा।

उजियारे में, अंधकार में,
कल कहार में, बीच धार में,
घोर घृणा में, पूत प्यार में,
क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में,
जीवन के शत–शत आकर्षक,
अरमानों को ढलना होगा।
कदम मिलाकर चलना होगा।

सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ,
प्रगति चिरंतन कैसा इति अब,
सुस्मित हर्षित कैसा श्रम श्लथ,
असफल, सफल समान मनोरथ,
सब कुछ देकर कुछ न मांगते,
पावस बनकर ढ़लना होगा।
कदम मिलाकर चलना होगा।

कुछ काँटों से सज्जित जीवन,
प्रखर प्यार से वंचित यौवन,
नीरवता से मुखरित मधुबन,
परहित अर्पित अपना तन–मन,
जीवन को शत–शत आहुति में,
जलना होगा, गलना होगा।
कदम मिलाकर चलना होगा।

संपादकीय

नई सरकार की चुनौतियां

पंद्रहवीं लोकसभा चुनाव में एनडीए को भले ही मात खानी पड़ी हो, लेकिन जिस तरह से एक स्पष्ट जनादेश आया है, उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ संकेत कहा जा सकता है। इस चुनाव में जहां अधिकतर क्षेत्रीय पार्टियों का जनाधिकार खिसक गया वहीं वाम मोर्चा के पैरों के तले से भी जमीन खिसक गई है। मायावती की महत्वाकांक्षा, लालू – पासवान का चौथा मोर्चा, सबकी अंततः हवा निकल चुकी है। चलिए जो भी हो हमें जनता के मत को स्वीकार करना चाहिए और संतोष इस बात को लेकर करना चाहिए कि देश को एक स्थिर सरकार मिल सकेगी। बाहुबलियों को भी जनता ने ठेंगा दिखा दिया है, जो भारतीय राजनीति के लिए शुभ संकेत कहा जा सकता है। संभवतः भविष्य में सांसदों के मोलभाव एवं जोड़–तोड़ की राजनीति से निजात मिल सकेगी और इस तरह से संसद की गरिमा भी बनी रहेगी। इस तरह लोकतंत्र के महाकुंभ का समापन हो गया।

आने वाली सरकार के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। विदर्भ और बुंदेलखंड के बाद अब हरित क्रांति का जनक माने जाने वाले पंजाब के किसान भी आत्महत्या की राह पकड़ने लगे हैं। हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने बठिण्डा और संगरूर जिलों के सर्वे में पाया कि इन जिलों के 89 फीसदी किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि–"60 हजार करोड़ रुपये के किसानों के कर्ज माफ कर देने, फसलों के समर्थन मूल्य भी बढ़ाने से क्या किसानों के दुख–दर्द समाप्त हो गए हैं। पंजाब की ताजा स्थिति को देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ग्रामीण भारत को विकास के भावी गंतव्य के तौर पर देखा जा रहा है और रिटेल सेक्टर के एक बड़े बाजार के तौर पर ग्रामीण भारत को देखा जा रहा है। क्या इन्हीं बातों को तरक्की का पैमाना माना जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ऐसे में कौन सा पैकेज यूपीए सरकार इस देश के किसानों को देगी? फसलों के दाम में कुछेक सौ रूपये बढ़ा देने से क्या किसान समृद्ध हो जायेगा? उस व्यवस्था का क्या जिसे अमेरिका के हाथों में लगातार गिरवी रखा जा रहा है? जिस देश के 70 फीसदी लोग खेती–किसानी पर निर्भर हों, वहां इस तरह के सवाल खाद्य सुरक्षा के अलावा करोड़ों लोगों के जीवन को भी प्रभावित कर रहे हैं। हमें भुलावे में नहीं रहना चाहिए कि किसान समृद्ध हो रहा है।

राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला भी दिन–ब–दिन गहराता जा रहा है। पाकिस्तान में तालिबानियों के कब्जे और उसके निहितार्थों की चर्चा हमने पहले भी की थी। नेपाल में भी अस्थिरता है। बांग्लादेशी घुसपैठ के प्रभाव को हम किशनगंज में देख ही रहे हैं, जहां स्थानीय आबादी घुसपैठियों की अपेक्षा काफी कम रह गई है। इसी तरह श्रीलंका में तमिलों पर अत्याचार का तांडव भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। चीन व्यावसाय एवं सुरक्षा दोनों स्तरों पर भारत के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसे में सुरक्षा के साथ साथ अर्थव्यवस्था को मंदी के दौर से उबारने की जिम्मदारी भी भावी सरकार पर रहेगी। आतंकी हमले न हों, इसके लिए भी कमर कसनी होगी।

इस बार चुनावों में युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जा रहा था। यूपीए के शासनकाल में जिस तरह से मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह ने एक तानाशाह की भांति शैक्षिक व्यवस्था को संक्रमित करने और मुस्लिम तुष्टिकरण की रणनीति अपनाई थी, उसकी समीक्षा कांग्रेस पार्टी को करनी होगी। देश की युवा पीढ़ी को शैक्षिक वातावरण एवं रोजगार मुहैया कराने की प्रतिबद्धता भी सरकार को दिखानी होगी। एक महत्वपूर्ण मामला विदेशों में जमा काले धन का है। इस पर सरकार का क्या रवैया रहता है, यह देखने की बात होगी। रोजगार गारंटी योजना को यूपीए की जीत का कारण बताया जा रहा है। लेकिन भूलना न होगा कि इसके योजनाकारों ने ही नरेगा के क्रियान्वन की खामियों को बार–बार उठाया है। ऐसे में उन खामियों को अलग रखकर इस योजना की बात करना बेमानी होगा।

कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि समस्याओं को आवरण से ढक देने से वे लुप्तप्राय अवश्य हो जाती हैं, लेकिन उनका दुष्प्रभाव यथावत् बना रहता है। भले ही नजर न आता हो। आवरण में ढंकी समस्याएं अपना विकराल रूप दिखाने लगें, इससे पहले ही हमें सचेत हो जाने की आवश्यकता है।

■

Sri Mohan Bhagwat is New Sarsanghachalak

Sri Mohanji Bhagwat hails from Chandrapur in Vidarbha, obtained his graduation in Veterenary Sciences from Punjabrao Krishi Vidyapeeth, Akola. Hailing from a family that had strong RSS roots he became a Pracharak in 1975.

After working underground during Emergency he was given responsibility of Akola in 1977 and become Pracharak of Nagpur and Vidarbha. He was Akhil Bharatiya Saha Shareerik Pramukh in 1987 and Shareerik Pramukh in 1991. In 1999 he was made the Akhil Bharatiya Pracharak Pramukh In 2000, Sri Mohan Bhagwat got elected as Sarkaryavah for three years. He got re-elected on the next two successive occasions in 2003 and 2006.

During his long career of 28 years as Pracharak he has travelled extensively in and outside Bharat and has guided countless activities and activists. He was nominated as the 6th Sarsanghachalak of RSS by Sri K.S. Sudarshanji during the Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha which held its meeting on 20-22 March 2009 at Nagpur.

Shri. Bhayyaji Joshi elected new Sarkaryavah

Sri Sureshji Joshi, popularly known as Sri Bhayyaji Joshi was Saha Sarkaryavah for last six years. Sri Bhaiyyaji Joshi is a widely travelled leader who has vast experience in both Shakha and Sewa activity. He has been guiding Sewa activities of the RSS for the last two decades.

Shri Dattareya Hosabale is new Sah Sarkaryavah

Shri. Dattatraya Hosabale, who was 'Akhil Bharatiya saha -Bouddhik Pramukh' for the last 6 years. He was National Organising Secretary of ABVP for long time.

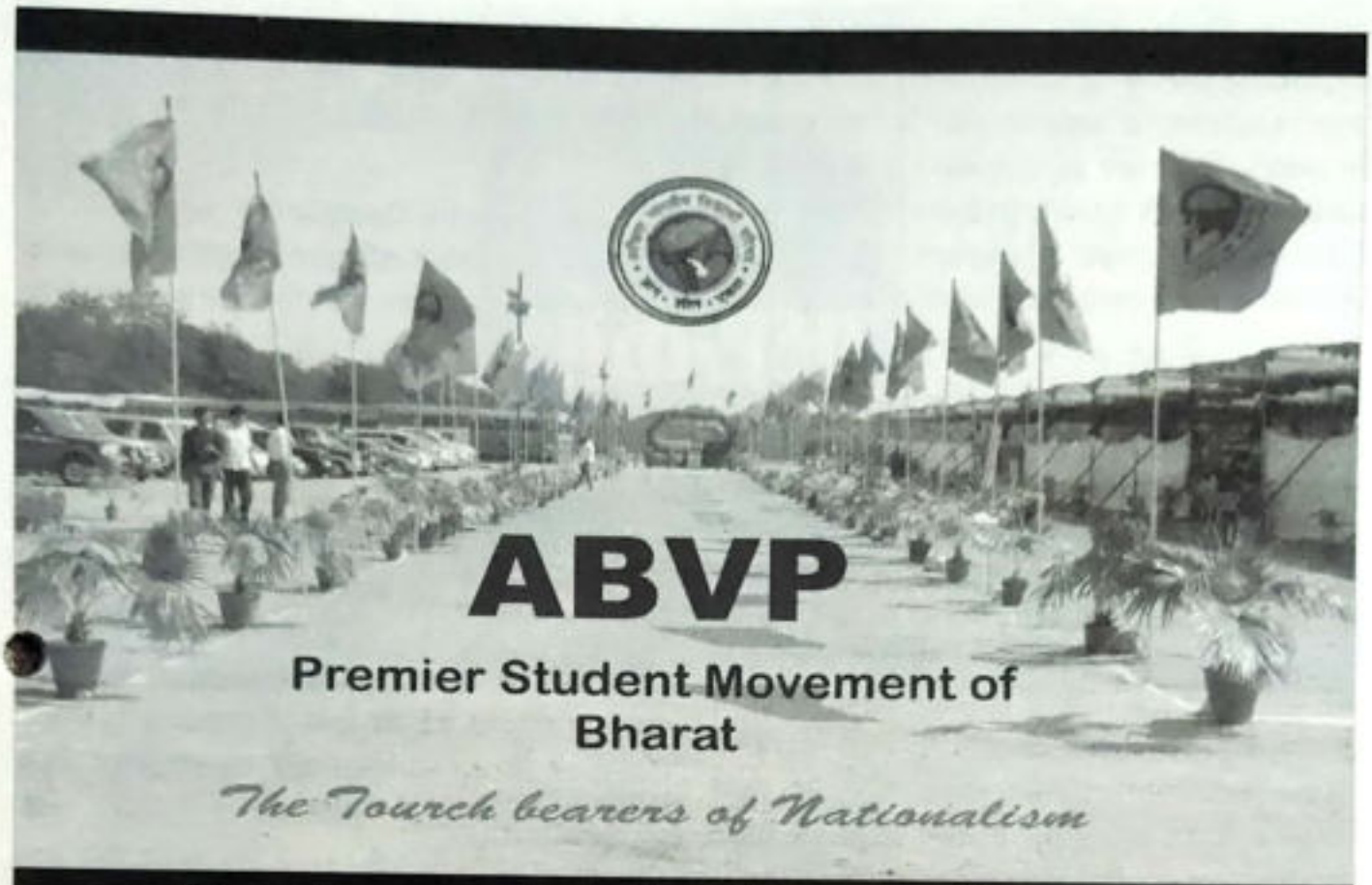

अभाविप के 60 वर्ष पूर्ती निमित्त छात्रों का आवाहन

समाज के लिए थोड़ा समय दें

आजकल आवागमन तथा अन्य सम्पर्क के साधन विपुल मात्रा में हो गए हैं । संचार क्रांति ने दुनिया का भौगोलिक अंतर कम किया है । पहले कुछ लोग ही दुनिया के दुसरे देशों के बारे में जानते थे, परन्तु अब सामान्य लोगों में भी यह जानने वाली संख्या लगातार बढ़ रही है । स्वाभाविक ही देशों की तुलना का विषय अब केवल अभ्यासकों, विशलेषकों या विशेष प्रवासी लोगों तक मर्यादित न रहकर आम जनता की भी चर्चा का विषय हो गया है ।

अब दुनिया के देशों की तुलना में हमारा देश कैसा है, यह स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं।

युवाओं के मन में एक सहज भाव से यह इच्छा जागृत होती जा रही है कि हमारा देश भी 'सुजलाम्–सुफलाम्' सुंदर बनाएँ ।

'अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद' इस देश का एक ऐसा आन्दोलन है जो कि अंग्रेजों से स्वाधीनता के पश्चात तुरन्त प्रारंभ हुआ। जिसका उद्देश्य हमारी हजारों वर्षों की उज्वल, भव्य तथा मानव जाति के हितार्थ किये कार्यों की परंपरा के अनुरूप पुनः भारत को उस से अधिक तेजस्वी स्वरूप देना था । एक ऐसा तेजस्वी स्वरूप जिस में भारत के हर बालक को तेजस्वी होने का मौका मिले, जिस से यह पुरे विश्व के कल्याण का पुरूषार्थ सिद्ध कर सके ।

उद्देश्य जितना भव्य, कार्य को भी उतने ही समर्पण भाव से देश के हजारों छात्रों ने सतत आगे बढ़ाया। यही कारण है कि अभाविप दुनिया का सबसे बड़ा एवं भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय छात्र संगठन बना है। ऐसे देशभक्ति जगाने वाले व छात्रों को समाज के प्रति आत्मीयता बढ़ाकर देश हितार्थ सक्रीय करने वाले संगठन को आने वाले

9 जुलाई 2009 को 60 वर्ष (1949–2009) पूरे हो रहे हैं।

इस निमित्त यह समयोचित होगा कि सभी छात्र अब इन प्रयासों को गति देने हेतु आगे आयें। अपने कॅरीअर के दबाव के होते हुए भी हर छात्र (11वीं कक्षा व उसके ऊपर) समाज के लिए कुछ समय जरूर दें, जिसमें समाज उपयोगी किसी भी कार्य को करने में अपना योगदान दें ।

समाज में ऐसी कई संस्थाएँ है जो गरीब छात्रों को पढ़ाती हैं, पुस्तकें देती हैं । स्वास्थ्य संदर्भ में कार्य करती हैं, या फिर कई संगठन हैं जो देश के हित में विज्ञान, तकनीकी, रोजगार, प्रशिक्षण जैसे उपक्रम चलाती हैं । कई लोग स्वास्थ्य, खेती जैसे कई विषयों में लोगजागरण में लगे है। आपात् परिस्तिति जैसे दुर्घटना के समय लोगों को सहयोग करने हेतु प्रशिक्षण लेना व दूसरों को देना ऐसे कई कार्य करणीय है। हम ऐसे किसी भी माध्यम से समाज के लिए छुट्टियों में दस – पंद्रह दिन या नियमित सप्ताह में दो–चार घंटे देकर अपना योगदान दे सकते हैं। समग्र परिवर्तन कोई संगठन नही कर सकता, बल्कि वह उसके अनुकूल वातावरण बना सकता है। जब ऐसे हजारों छात्र–छात्राऐं अपना थोड़ा – थोड़ा समय लगायेंगे तो हम निरक्षरता जैसी कई समस्याओं को बहूत कम समय में निपट सकते हैं ।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् कई संस्थाओं की सहायता से आप जैसे हसारों छात्रों को देश एवं समाज के लिए कुछ करने का मौका जरुर दे सकती हैं।

भारत आज दुनिया में सर्वाधिक युवाओ का देश है। कई क्षेत्रों में हम सभी मिलकर प्रगति भी कर रहे हैं परन्तु इस विकास यात्रा में हमें हर देशवासी को शामिल करना है, सभी के जीवन में खुशहाली लानी है । यह जरूर देखें कि हम कुछ आगे बढ़ें, लेकिन हजारों पीछे न छूट जाएं। इसलिए हमें सरकारों को दोष देना व परिस्थिति की वियशता का बहाना छोड़ना होगा ।

आओ हम सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की इस उमंग भरी 60 वर्ष की यात्रा में उत्साह से जुटें तथा संकल्प करें कि हम भी अपना कुछ ना कुछ समय देकर देशवासियों के उत्थान में सहयोगी बनें । ■

चुनाव सम्पन्न - जिम्मेदारी शेष

दिनांक 16 मई, 2009, दोपहर के बाद चुनावों के परिणाम साफ हो गये व कुछ माह से प्रारंभ अलग–अलग भविष्यवाणियों की समाप्ति हो गयी। फिर पुनः चुनाव लगभग शांतिपूर्वक सम्पन्न हुए। आरोप–प्रत्यारोपों का दौर चला परन्तु अंततः चुनाव आयोग द्वारा घोषित जनता के आदेश को सभी दलों ने स्वीकार करते हुए लोकतंत्र व चुनाव प्रक्रिया के प्रति सम्पूर्ण निष्ठा प्रकट की। यह हमारे देश के लिए निश्चित ही एक बड़ी सफलता है। विशेषकर हमारे अधिकतम पड़ोसी देशों में जहां लोकतंत्र खतरे में हैं । इन सफल चुनावों का महत्व और ही बढ़ जाता है ।

नया मंत्रीमंडल, विपक्ष के नेता का चयन, सभी दलों द्वारा प्रतिक्रियाएँ यह दौर भी जल्द ही पूरा हो जायेगा। समाचार माध्यम अब अन्य समाचारों की जोड में लग जायेंगे व जनता भी दो माह की इस बहस से थोड़ी दूर हो जायेगी । जनता के बीच उपलब्ध नेता भी राजधानियों में व्यस्त हो जायेंगे । यह तो स्वाभाविक ही है। परन्तु महत्वपूर्ण है कि देश की सामान्य जनता की आकांक्षाएँ, आवश्यकताओं एवं चिंताओं के बारे में क्या होगा ? यह एक अहम् सवाल है, जिसका समाधान हम सभी को ढूँढना होगा। जागृत मतदाता जो हमेशा सतर्क है, मतदान के समय भी एवं उसके बाद भी समाधान बन सकता है ।

चुनाव परिणामों के कई अर्थ लगाये जा रहे हैं। कुछ बातें तो एकदम

– सुनील आंबेकर –
राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अभाविप

साफ उभरकर सामने आयी हैं, जैसे जनता का कांग्रेस व उसके गठबंधन की तरफ झुकाव, वामपंथियों को नकारना तथा श्री लालू प्रसाद यादव व श्री रामविलास पासवान जैसे नेताओं से भरोसा समाप्त होना। एनडीए एवं विशेषकर भाजपा के प्रति झुकाव में कमी भी विशेष रूप से नजर आ रही है। अपने फायदे व नुकसान की समीक्षा करने में सभी लगे हैं लेकिन जनता का फायदा व नुकसान इसकी समीक्षा भी जरूरी है।

सबसे पहले बात है कि मतदाताओं का मतदान करने के प्रति उदासीन रहना, यह चिंता का विषय है। कई स्थान पर 40 प्रतिशत के आसपास मतदान हुआ। मतदान से सार्थक सरकारें बनती हैं यह विश्वास जगाने हेतु सभी राजनैतिक दलों, मीडिया, सामाजिक संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। दलों को अच्छे उम्मीदवार देना, मीडिया एवं सामाजिक संगठनों द्वारा सरकार पर अंकुश रखते हुए भी गंभीर विचार–विमर्श के लिए जनता के बीच माहौल बनाना होगा । जब तक लोक जागरण के माध्यम से जाति, स्थानीय, हितसंबंध, लालच या मजबूरी आदि मुद्दों पर मतदान की संभावना समाप्त नही होती तब तक सही उम्मीदवार चयनित होना कठिन रहेगा।

जनता की इस उदासीनता के कारण राजनैतिक दलों के घोशणापत्र एक औपचारिकता बन गए हैं । दूसरी बात सैक्यूलरिज्म / धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने की घातक प्रवृत्ति का दर्शन ऐसे सभी तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों द्वारा अनुभव में आया । स्वार्थवश देश में तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों ने अल्पसंख्यक तृष्टीकरण की हद पार कर दी। यह चित्र सामने आया कि मतों के स्वार्थ में देश के हितों के साथ भी इनके द्वारा समझौता संभव है ।

सच्चर कमेटी लागू करते हुए एक भयंकर अध्याय का प्रारम्भ इस देश में ऐसे दलों ने किया है। स्वयं को सेक्यूलर कहने वाले घोर साम्प्रदायिक हो गये हैं, यह चिंता का विषय है। अर्थात निर्णय देश की जनता का है, हो सकता है शायद वह वर्तमान की रोजमर्रा की शांति को महत्व देती हो तथा विवादास्पद मुद्दों को टालना चाहती हो। बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार पर बनी असम की पार्टी एयूडीएफ (AUDF) ने और प्रगति करते हुए अब लोकसभा में 2 स्थान प्राप्त की हैं व कई स्थानों पर अच्छे खासे मत प्राप्त किये हैं ।

जय हो.....ना युपीए की ना एडीए की जय हो तो बस मेरे भारत माँ की ।

दूसरी तरफ दार्जिलिंग जहां कभी गोरखा लैण्ड के लिए सशस्त्र भूमिगत आन्दोलन चला था, वहां के लोगों ने अपनी मांगों के लिए लोकतंत्र में आस्था दिखाकर राष्ट्रीय स्तर के राजनैतिक दलों से जुड़कर काफी सकारात्मक पहल की है । नक्सलियों द्वारा चुनाव दौरान कराई गयी हिंसा भयंकर थी, परन्तु छत्तीसगढ़ से झारखण्ड तक लोगों ने इसके प्रभाव से बाहर निकल कर काफी साहस का प्रदर्शन किया है ।

अभी परिस्थितियों में चुनावों में उपयोग आया करोड़ों का धन, विदेशी बैंकों से काला धन वापस लाने के प्रति उदासीनता से स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार कम होने की बजाई बढ़ने के आसार ज्यादा हैं । ऐसे में देश के सरकारों पर निर्भरता व परिस्थिति के सामने विवशता से काफी नुकसान होगा।

कुछ दल व मीडिया यह दावा कर रहे हैं कि युवा नेतृत्व उभर कर आ रहा है लेकिन सच यह नही है । कोई दल यह दावा करे तो समझ में आता है लेकिन निरपेक्ष कहने वाला मीडिया या जानकार विश्लेषक ऐसी बात कहते हैं तो आश्चर्य लगता है । वे ऐसा कहकर जनता को भी भ्रमित कर रहे हैं। देश मे सर्वाधिक संख्या मे युवा हैं व उनमें कर्तव्य की कमी नही है । परन्तु युवा नेतृत्व के नाम पर उपर से नीचे तक परिवारवाद ही नजर आता है। मुम्बई या दिल्ली के सारे विजयी युवा चेहरे अपने परिवार के ही द्वारा उभरे नेता हैं। पारम्परिक प्रभाव, धन–बल, बाहुबल एवं जाति के आदार पर दलों पर परिवारों का कब्जा है एवं चुनाव इतने खर्चीले हैं कि आम लोगों मे से नैसर्गिक पद्धति से युवा नेतृत्व उभर कर आना काफी मुश्किल हो गया है । छात्रसंघ चुनाव या तो बंद हैं या उनका स्वरूप भी कुछ ऐसा ही रहा है, जिससे नये युवा नेतृत्व की संभावनाएँ और ओझल हो गयी हैं ।

कम से कम छात्र–युवाओं को ऐसे प्रचारों के प्रभाव में आकर इन्हीं तथाकथित युवा नेताओं पर निर्भर नही होना चाहिए क्योंकि वह सारे जनता से नही अपितु परिवारवाद के हित संबंधों से बंधे हैं । इसलिए उनसे कुछ ठोस परिवर्तनों की आशा करना बेनामी साबित होगी ।

इसलिए छात्र–युवाओं देश के हित में सकारात्मक पहल करते हुए जनहित में सक्रिय नये युवा नेतृत्व को हर क्षेत्र में उभारना होगा। चुनाव संपन्न हो गये लेकिन हमारी जिम्मेदारी शेष है। देश के छात्रों को अपनी भूमिका का निर्वाह करना होगा। छात्रशक्ति को अपनी भूमिका का निर्वाह करना होगा । छात्रशक्ति को सत्ता को प्रश्न पूछने होंगे, अंकुश लगाना होगा। जैसा चल रहा है, चलने दो की नीतियाँ छोड़कर आवाज उठानी होगी। एक व्यापक छात्र आन्दोलन की देश प्रतीक्षा कर रहा है।

सकारात्मक पहल व सत्ताओं पर अंकुश दोनों कार्य कराने की जिम्मेदारी लेकर परिसरों को सक्रिय होना होगा । इससे चुनाव से बनी सरकारें अधिक सार्थक बनेंगी व उनकी जवाबदेही बढ़ेगी तथा साधारण जनता राहत की सांस लेगी । भारत के पास बहुत शक्ति है युवाओं की, आवश्यकता है उसे सक्रिय होने की ।

जय हो....ना युपीए की ना एडीए की
जय हो तो बस मेरे भारत की।

उच्च शिक्षा में लोचे बड़े

– आशीष कुमार 'अंशु' –

उच्च शिक्षा पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के पूर्व अध्यक्ष यशपाल की देखरेख में बनी समिति ने हाल में ही अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। फरवरी 2008 में बनी इस समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 40 सालों से उच्च शिक्षा में बड़े सुधार नहीं हुए हैं। उच्च शिक्षा में निजी संस्थाओं की बढ़ती भागीदारी पर समिति ने माना कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उनका अहम योगदान है। लेकिन फीस को लेकर उनके उनपर किसी तरह का नियंत्रण ना होने पर समिति ने चिन्ता भी व्यक्त की। समिति मानती है कि फीस से संबंधित कुछ कड़े नियम होने चाहिए। जिससे संस्थान मन माफिक फीस में वृद्धि ना करें और आम छात्र भी यहां पढ़ सकें। रिपोर्ट में निजी विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालयों को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है कि इसमें गैर कानूनी रुप से वसूली जाने वाली कैपिटेशन फीस की रेंज काफी ज्यादा है। ताज्जुब की बात यह है कि रेग्युलेटरी एजेन्सी भी गैर कानूनी कैपिटेशन और सालाना फीस पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रही है।

समिति से जुड़े दिल्ली विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्राध्यापक अपूर्वानन्द ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को वर्तमान व्यवस्था का एक सुन्दर विकल्प बताया। अपूर्वानन्द ने कहा कि 'आज के समय में शिक्षा एक व्यवसाय का रुप ले चुकी है। हमारे पास इस शिक्षा व्यवस्था का एक सुन्दर विकल्प था, सरकारी शिक्षा व्यवस्था का। अब यह बता पाना मुश्किल है कि पहले इस व्यवस्था में खामी आई, उसके बाद हमने इसे छोड़ा या फिर हमने इसे छोड़ा इसलिए व्यवस्था में कमी आई।'

समिति ने पिछले कुछ सालों में निजी विश्वविद्यालयों को मिल रहे डिम्ड विश्वविद्यालय के दर्जे पर भी सवाल खड़े किए और इसपर रोक लगाए जाने की अनुशंसा की। साथ ही यह भी कहा कि जो विश्वविद्यालय नियम–कायदों पर खरी ना उतरे, तीन साल के बाद उनके डीम्ड का स्टेटस वापस ले लिया जाए। अब देखिए ना, कुछ निजी व्यावसायिक महाविद्यालयों को जैसे ही विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, उन्होंने अपनी क्षमता से पांच से छह गुना अधिक विद्यार्थी लेने शुरू कर दिए। जबकि इसके लिए उन्होंने अपनी सुविधाओं में कोई इजाफा नहीं किया।

कैपिटल फीस के रुप में लाखों रुपए की अवैध वसूली की जाती है। रेग्यूलेटरी संस्थाएं इस फीस पर लगाम कसने में असफल हुई हैं। 1956–1990 के बीच 29 संस्थाएं ही डीम्ड विश्वविद्यालय में तब्दील हुई। पिछले 15 सालों (1993–2008) में 63 जबकि सिर्फ पांच सालों (2003–2008) के दौरान 36 संस्थाओं को डीम्ड का दर्जा मिला। इस समय कुल 108 निजी डीम्ड विश्वविद्यालय हैं।

यशपाल समिति ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं:

- यूजीसी, एआईसीटीआई जैसी रेग्यूलेटरी बॉडीज को हटाकर कमिशन फॉर हायर एजुकेशन बनाया जाए। यह कमिशन देश में हायर एजुकेशन के लिए ठोस नीति बनाए।
- डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने और वहां पर शिक्षा के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए कड़े नियम हों।
- स्टेट यूनिवर्सिटी की ओर भी पूरा ध्यान दिया जाए, और सेन्ट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी में भेदभाव ना हो। स्टेट यूनिवर्सिटी को उचित फंड मिले।

उच्च शिक्षा में निजी विश्वविद्यालय और संस्थाओं में आर्थिक तौर पिछड़े छात्रों के लिए कोई जगह नहीं है। क्या इस देश में जो गरीब है, उसे प्रतिभाशाली होने के बावजूद पढ़ने का अधिकार नहीं है। यहां मेडिकल, इंजिनियरिंग अथवा इस तरह के दूसरे विषयों के लिए वसूले जा रहे पैसों का कोई बुनियादी आधार नहीं है। फीस तय करते समय नियम और कायदों की जमकर धज्जी उड़ाई जाती है। ये सभी बातें प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में गठित कमिटी ने कही है, जिसका गठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किया था। ■

संवैधानिक पदों की गरिमा का सवाल

– उमाशंकर मिश्र –

सत्तासीन राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल अधिकारियों एवं व्यक्तियों को आसीन करने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर प्रतिभा पाटिल, मनमोहन सिंह और नवीन चावला जैसे अपने पक्षधर एवं 10 जनपथ के प्रति वफादार लोगों को बिठाया है, उससे इन पदों की गरिमा माटी में मिल गई है।

कांग्रेस और यूपीए के घटक दलों ने मिलकर 2004 में सरकार बनाने का जब फैसला किया तो माना यह जा रहा था कि सोनिया गांधी ही प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने जा रही हैं। लेकिन जब उनके विदेशी मूल के होने की बात आई तो उन्हें अंततः झुकना पड़ा और उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से इंकार कर दिया। ऐसे में सोनिया गांधी को त्याग की देवी के रूप में महिमामंडित करने का अवसर कांग्रेस और उसके चाटुकारों को मिल गया। इस बीच प्रधानमंत्री पद के लिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश की जाने लगी, जिस पर यूपीए के घटक दलों के साथ–साथ इस पद की आस में कांग्रेस के भीतर बैठे नेताओं की जुबान न खुल सके। तभी मनमोहन सिंह का नाम इस पद के लिए तय होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री पद के अन्य दावेदारों अर्जुन सिंह या फिर प्रणब मुखर्जी जैसों की अपेक्षा मनमोहन सिंह को 10–जनपथ से आसानी से संचालित किया जा सकता था। कांग्रेस ने यहीं से संवैधनिक पदों की पदावनति का सिलसिला चला दिया। देश को एक रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री देने के बाद, राष्ट्रपति पद पर आरोपों से घिरी होने के बावजूद प्रतिभा पाटिल को और अब अपने वफादार नवीन चावला को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर बिठा दिया है।

राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की तो उम्मीदवारी को लेकर ही नैतिक सवाल उठाये गए थे। जलगांव स्थित संत मुक्ताई चीनी सहकारिता बोर्ड की अध्यक्षा प्रतिभा पाटिल पर एक करोड़ 75 लाख की देनदारी उस समय थी। सवाल यह है कि बैंक से लोन लेने के संबंध में एक आम आदमी और एक संवैधानिक पद के दावेदार नेता के बीच क्या कोई फर्क नहीं होता? यही नहीं प्रतिभा पाटिल पर 2005 में बीजी पाटिल नामक व्यक्ति की हत्या के आरोपी अपने भाई जयंत पाटिल को बचाने के लिए अपनी राजनीतिक ताकत के गलत इस्तेमाल के भी आरोप लगे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जो व्यक्ति निजी हितो को ऊपर रखते हुए गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल रहा हो, वह राष्ट्रहित के साथ न्याय कैसे कर पायेगा? इसके अलावा उनके पति देवी सिंह पाटिल पर भी एक स्कूली शिक्षक को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप लगे हैं। यही नहीं प्रतिभा पाटिल पर चीनी मिल के कर्ज घोटाले, इंजीनियरिंग कॉलेज में फंड के घपले और उनके परिवार पर भूखंड हड़पने के संगीन आरोप हैं। इसके बावजूद श्रीमती पाटिल आज देष के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विद्यमान हैं। रही बात उनके सामान्य ज्ञान एवं प्रतिभा की तो इस भी सवाल उठे हैं। राजस्थान की एक सभा में उन्होंने कहा था कि "राजस्थान की महिलाओं को मुगलों से बचाने के लिए पर्दा प्रथा आरंभ हुई।" इस पर खूब बवंडर मचा। इतिहासकारों ने तो वर्तमान राष्ट्रपति के इतिहास ज्ञान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि "प्रतिभा पाटिल का इतिहास ज्ञान शून्य है।" यह बस जानते हुए भी कांग्रेस पार्टी द्वारा उन्हें राष्ट्रपति पद पर बिठाने के लिए सारे घोड़े छोड़ देना दर्शाता है कि यह पद केन्द्र की राजनीति में कितना अहम् होता है। लेकिन राष्ट्रपति पद की दावेदारी की उनकी योग्यता का मुख्य आधार 10 जनपथ से उनकी नज़दीकी को माना जाता है। जिसके कारण डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जैसी महान विभूति और उपराष्ट्रपति रह चुके भैरो सिंह शेखावत का अनुभव एवं बेदाग छवि भी बौने साबित कर दिये गए।

प्रतिभा पाटिल की उम्मीदवारी इसलिए भी बनती थी, क्योंकि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरह उनका रिमोट कंट्रोल अपने पास रख सकती थी। डॉ. कलाम या फिर भैरो सिंह शेखावत के इस पद पर आसीन होने से संसद हमले के आरोपी अफजल गुरू को अब तक फांसी हो चुकी होती। उल्लेखनीय है कि अफजल को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है और उसकी सजा माफी की

अपील राष्ट्रपति के पास लंबित है। राष्ट्रपति ने यह फाईल केन्द्र सरकार के पास भेज दी और तब से फाईल वहीं दबी हुई है। यह बताना न होगा कि यह सब यूपीए सरकार वोट बैंक की राजनीति के तहत कर रही है। क्योंकि यदि अफजल को उसके शासन में फांसी हो जाती है तो मुस्लिमों के वोट खिसकने का ख़तरा उन्हें सता रहा है। क्या वोट के लिए यह देश के साथ गददारी नहीं है? आखिर कब तक जनता की आंखों में धूल झोंककर कांग्रेस देश की जड़ों को खोखला करती रहेगी?

इसी तरह का एक और पद मुख्य चुनाव आयुक्त का होता है। संवैधानिक दृष्टि से भारतीय लोकतंत्र में इस पद की गरिमा एवं निष्पक्षता महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसी संस्था पर देश की जनता द्वारा चुनी गई सरकार के गठन का दायित्व होता है। लेकिन यहां भी कांग्रेस के विश्वस्त माने जाने वाले नवीन चावला ने हाल ही में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन. गोपालास्वामी की जगह ली है। नवीन चावला को भी सोनिया गांधी एवं उनके परिवार का करीबी माना जाता है। इसी बात को लेकर राजनीतिक हलकों में चावला की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े होने लगे। कुछ मामलों पर गौर करें तो चुनाव आयोग का पक्षपात रवैया जाहिर हो जाता है। आयोग की भूमिका को लेकर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने वर्तमान लोकसभा चुनावों के दौरान उसे कटघरे में खड़ा कर दिया। राजनीतिक विरोधियों की आधारहीन शिकायतों को मुददा बनाकर आयोग द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को हटाए जाने पर मायावती ने सवाल खड़े कर दिये।

जिस तरह से चुनाव आयोग द्वारा बीजेपी के युवा नेता वरूण गांधी के खिलाफ सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने की बात पर पार्टी हाईकमान को निर्देश जारी किया गया, क्या आचार संहिता के मामले पर कांग्रेस और यूपीए के घटक दलों पर भी आयोग ने इसी तरह के कदम उठाये हैं? यह एक उल्लेखनीय सवाल है। केन्द्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा वरूण गांधी पर रोड रोलर चलवाने की बात कहना, दिग्विजय सिंह द्वारा मायावती को सीबीआई जांच की धमकी, राबड़ी देवी द्वारा सार्वजनिक मंच से नीतिश कुमार एवं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह पर अशोभनीय टिप्पणी और आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.श्रीनिवास द्वारा अल्पसंख्यक सभा में हिन्दुओं के हाथ काट देने की बात कहना क्या आचार संहिता का उल्लंघन नहीं था? लेकिन यहां तो तमाम साक्ष्य उपलब्ध कराये जाने के बाद भी आयोग की प्रतिक्रिया आने में ही 10 दिन लग गए। अंततः प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी डी. सुब्बाराव ने चेतावनी देकर खानापूर्ति कर ली। यहां सवाल यह उठता है कि आखिर भाजपा के वरूण गांधी की जब बात आती है तो आयोग यह सहानुभूति क्यों नहीं दिखा पाता है? भविष्य में चुनाव आयोग के ऐसे पक्षपातपूर्ण रवैये से इस संवैधानिक संस्था की गरिमा क्या कायम रह पायेगी? इन्हीं बातों को लेकर राजनीतिक दलों ने नवीन चावला की भूमिका को संदेहास्पद माना था।

उल्लेखनीय है कि मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला पर अपने परिवार के नाम से स्वयंसेवी संगठन चलाने का आरोप है। यही नहीं इस संगठन के लिए कई कांग्रेस सांसदों की निधि से पैसे दिये जाने की बात भी सामने आई है। सवाल यह है कि कांग्रेस सांसदों की निधि से पैसा लेने वाले नवीन चावला क्या उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई कर पाएंगे? इसी बात को लेकर नवीन चावला जब चुनाव आयुक्त थे तभी से उन्हें हटाये जाने की मांग की जाती रही है।

चावला की ऐसी संदिग्ध छवि के चलते करीब 200 सांसदों ने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. कलाम से चावला के खिलाफ कार्रवाई के लिए मांग की थी। जिस पर डॉ. कलाम ने सरकार की राय मांगी तो यूपीए सरकार ने जांच की जिम्मेदारी मुख्य चुनाव आयुक्त को सौंपने की बजाय एटार्नी जनरल मिलन बैनर्जी को सौंप दी। इस तरह यह जांच भी सवालों के घेरे में आ गई। अंततः एटार्नी जनरल ने नवीन चावला को क्लीन चिट दे दी। लेकिन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन. गोपालास्वामी ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और नवीन चावला को पद से हटाने की सिफारिश कर डाली। कांग्रेस इससे बौखला गई और सवाल खड़ा किया जाने लगा कि "क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने सहकर्मी को हटाने का अधिकार है?"

इसी बीच प्रख्यात संविधानविद् सुभाष कश्यप की इस मामले पर सटीक प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि "मुख्य चुनाव आयुक्त एन. गोपालास्वामी के रिटायर होने के बाद जरूरी नहीं कि सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त (नवीन चावला) को ही मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाये, सरकार चाहे तो इस पद पर किसी भी योग्य व्यक्ति को आसीन कर सकती है।" सुभाष कश्यप ने यह भी साफ कर दिया कि "संवैधानिक प्रावधानों एवं सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के आधार पर किसी भी निर्वाचन आयुक्त को सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है।" लेकिन इन तमाम तर्कों को दरकिनार कर यूपीए सरकार ने नवीन चावला को इस पद पर बैठाकर इस पद की गरिमा को धूल धुसरित कर दिया है। बहरहाल जब राष्ट्रपति एवं चुनाव आयुक्त दोनों ही सरकार के हों तो भला कांग्रेस राजनीति क्यों नहीं करेगी।

आज जब देश में एक बार फिर लोकसभा चुनाव का महासमर चल रहा है तो एनडीए सरकार में प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की बेहद याद आती है। अटल जी एक सर्वमान्य, लोकप्रिय एवं सख्त निर्णय लेने वाले नेता माने जाते हैं। अटल जी की वाक्पटुता, उनकी कार्यकुशलता एवं अनुभव का लोहा उनके विरोधियों ने भी माना है। अटल जी के भाषणों को सुनने के लिए लोग आतुर रहते थे। संसद में जब भी वे बोलते तो पूरा सदन सन्न होकर सुनता था। विदेशी दबाव के आगे अटल जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कभी घुटने नहीं टेके। देश के शीर्ष ऐसे मजबूत इरादों के व्यक्ति के होने से देश की गरिमा बढ़ गई थी। लेकिन दूसरी ओर वर्तमान यूपीए सरकार ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी गिराया है। यहां भी कांग्रेस और सोनिया गांधी के वफादार मनमोहन सिंह को बैठा दिया गया है। जबकि मनमोहन सिंह के पास अपना कोई जनाधार नहीं है और वे राज्यसभा से चुनकर आते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि वे एक विख्यात अर्थशास्त्री एवं बेदाग छवि के व्यक्ति माने जाते हैं। लेकिन उनका सीधापन और परिस्थितिनुकूल निर्णय लेने में 10 जनपथ पर निर्भर होना प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। परमाणु करार के मुद्दे पर यूपीए की अमेरिकापरस्ती जाहिर हो गई। अटल जी जैसे व्यक्ति देशहित को ध्यान में रखकर अमेरिका के आगे घुटने कभी नहीं टेकते। लेकिन मनमोहन सिंह ने ऐसा करके प्रधानमंत्री पद के सम्मान और राष्ट्रहित दोनों को नुक्सान पहुंचाया है। यूपीए के सहयोगी वाम दलों ने भी इस मसले पर सरकार का साथ छोड़ दिया और सरकार अल्पमत में आ गई, लेकिन कांग्रेस की छुद्रता सांसदों की खरीद फरोख्त के रूप में जग-जाहिर हो गई। सोनिया गांधी और कांग्रेस को हमेशा गरियाने वाले अमर सिंह से सरकार बचाने के लिए समझौता करना कांग्रेसियों के बेपानी एवं सत्तालोलुपता की हकीकत बयां कर देता है।

कांग्रेस पार्टी में अन्य अनुभवी एवं जनाधार वाले नेता भी थे, लेकिन वे मनमोहन सिंह की तरह सीधे-साधे नहीं थे और 10 जनपथ के इशारों पर संचालित होंगे, इस पर संदेह था। इसलिए प्रधानमंत्री पद पर मनमोहन सिंह जैसे कमजोर व्यक्ति को सोची समझी रणनीति के तहत बिठा दिया गया। ताकि उनका कंट्रोल भी सोनिया गांधी के पास बना रहे। लोकसभा चुनावों के दौरान जब भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार लालकृष्ण आडवाणी ने मनमोहन सिंह को मुद्दों पर आधारित बहस के लिए आमंत्रित किया तो वे पीछे हट गए। देश की चुनौतियों एवं समस्याओं पर बहस से भी कतराने वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार यूपीए ने बनाया है। ऐसे व्यक्ति से आखिर क्या अपेक्षा की जा सकती है। देश के नेतृत्व के लिए मनमोहन सिंह उपयुक्त व्यक्ति हों अथवा नहीं, लेकिन यह तो तय हो चुका है कि कांग्रेस अध्यक्षा के हितों को पोषित करने वाले वे सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मनमोहन सिंह की अंतरात्मा भी उन्हें नहीं धिक्कारती? अगर देशहित एवं संवैधानिक निर्णय लने की कूबत उनमें नहीं है तो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी से उन्हें अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। ताकि इस पद की गरिमा बनी रहे।

यूपीए सरकार द्वारा सीबीआई दुरूपयोग को लेकर भी सवाल उठे हैं। कांग्रेस के युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी के हालिया बयान से यह बात साफ हो जाती है। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि सत्तासीन दल सीबीआई का दुरूपयोग करते हैं। 1984 में सिखों के नरसंहार के आरोपियों सज्जन कुमार एवं जगदीश टाईटलर को क्लीन चिट दिलाकर चुनावी लाभ उठाने की कोशिश कांग्रेस को महंगी पड़ गई और जनदबाव के चलते इन दोनों उम्मीदवारों को अपने नाम वापस लेने पड़ गए। लेकिन जब चुनाव के अंतिम चरण में कांग्रेस को अपनी हार का भय सताने लगा बोफोर्स तोप सौदे में दलाली के संबंध में आरोपित सोनिया गांधी के करीबी माने जाने वाले क्वात्रोची को भी सीबीआई से क्लीनचिट दिला दी गई। ताकि कांग्रेस के दामन से देश के साथ की गई दलाली का दाग मिटाया जा सके। कुल मिलाकर यह साफ हो गया है कि यूपीए सरकार ने अपनी हितपूर्ति के लिए देश की विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को माटी में मिला दिया है। ■

UGC Norms Equate Ragging With Rape

The merciless killing of a 19-year-old youth Aman Kachroo by his seniors in Himachal Pradesh, which is known for its splendid natural beauty and general people's myth that fanatic ragging, can never occur in such peaceful regions got shattered with it. Add to it this the fact that the incident happened in a medical college from where our society will get the future doctors who will serve us tomorrow and try to be our saviours, but some of the would be saviours of this college decided to become savages first and decided to commit savagery in a brutal way in the form of cruel ragging, ultimately killing Aman. Do we need such savage and brutal doctors in the future to serve our society?

Ragging is a practice involving human rights abuse in educational institutions in South Asia, the worst forms of which are found in engineering, medical and military colleges. It is committed by 'senior' students (those in second year or higher) upon 'fresher', in and outside on-campus residence, or hostels.

But most 'survive' ragging, and are taken aback with the transformation of enemy into friend, and are only too happy to forget their trauma and move on. Ragging is thus the fresher's passport to joining the college/hostel community, and many trudge along the ragging period because they wish to belong to the college community. Those who rebel against it are ostracised; retribution may also take the form of physical assault, leading to fatal injuries as we have already seen in the case of Aman Kachoo.

Some states in India have anti-ragging laws. The major boost to anti-ragging efforts was given by a landmark judgment of the Supreme Court of India in May 2001, in response to a public interest litigation (PIL) filed by the Vishwa Jagriti Mission.

This is how the Supreme Court of India defines ragging: Any disorderly conduct whether by words spoken or written or by an act which the effect of teasing, treating or handling with rudeness any other student, indulging in rowdy or in-disciplined activities which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in a fresher or a junior student or asking the students to do any act or perform something which such student will not do in the ordinary course and which has the effect of causing or generating a sense of shame or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of a fresher or a junior student.

In an attempt to stamp out ragging in educational institutions, University Grants Commission (UGC) has decided to recommend

that ragging be treated as a cognizable offence on par with rape. Significantly, even "...fresher who do not report the incidents of ragging either as victims or as witnesses shall also be punished suitably," says the UGC's policy draft on curbing the menace of ragging.

A senior UGC official said the regulations, when notified, would serve as a framework on the basis of which the police could take action on complaints from educational institutions and students. "The Supreme Court had entrusted to the UGC the responsibility of preparing the draft regulations," he said.

"The institution shall strictly observe the provisions of the Act of the Central government and the state governments, if any, or if enacted, considering ragging as a cognizable offence under the law on a par with rape and other atrocities against women and ill-treatment of persons belonging to the SC/ST, and prohibiting ragging in all its forms in all institutions," says the draft regulation. Currently, not many states have enacted legislation banning ragging, which makes it difficult for law enforcers to book culprits. The regulations are expected to help provide the legal framework for the police to act quickly.

According to UGC's proposals, ragging in all its forms will be totally banned "in the entire institution, all its premises (academic, residential, sports, canteen, etc) whether located within the campus or outside, and in all means of transportation of students whether public or private". As per the regulations, even abetting ragging is an offence.

The UGC has recommended rigorous imprisonment (RI) for three years, besides a fine of Rs 25,000 for those caught in the act and urged state and Central governments to enact a law against ragging wherever it does not exist.

In exercise of the powers conferred by clause (g) of Sub section (1) of Section (26) of University Grants Commission Act 1956, the University Grants Commission hereby makes the following Regulation namely:

'These regulations shall be called the " UGC Regulations on curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009"; they will come into force with immediate effect and the regulations shall apply to all the universities established or incorporated by or under a Central Act, a Provisional Act, to all institutions. The latest draft of 20th April 2009 of the Apex Commission puts the following ingredients of ragging, which are punishable under the court of law.

These are:

Abetment to ragging,Criminal conspiracy to rag, Unlawful assembly and rioting, Public nuisance created during ragging, Violation of decency and moral thought , Injury to body ,Wrongful restrain, Wrongful confinement, Use of criminal force, Assault as well as sexual offences or unnatural offences, Extortion, Criminal trespass, Offences against property,Criminal intimidation, etc.

A copy of the UGC Draft Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, has been circulated to heads of all higher educational institutions in the country to elicit their opinions.

To facilitate easy reporting about ragging, students should have unrestricted TV access to mobile phones and public phones in hostels and campuses, except in classrooms, seminar halls and libraries where jammers will be installed, the droll suggests. The apex higher education body has also promised financial incentives to institutions which succeed in putting an end to the menace that has taken the lives of dozens of young students over the years. ■

अभाविप की शिक्षा विषयक गोष्ठी

शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता

–विष्णुदत्त शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री, अभाविप

गत दिनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा भोपाल (मध्य प्रदेश) में 'उच्च शिक्षा में सेमेस्टर पद्धति अनुभव एवं दिशा' विषयक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में बोलते हुए अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि आज शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। सेमेस्टर पद्धति लागू करने के पीछे उद्देश्य यही था कि छात्र प्रतिस्पर्धा के युग में दुनिया के समकक्ष खडा हो। ऐसी आशा की गयी थी कि शिक्षा के साथ युवाओं का व्यक्तित्व विकास भी होगा लेकिन सरकार की जल्दबाजी से यह निर्णय अदूरदर्शी साबित हुआ। उन्होंने कहा कि सेमेस्टर पद्धति लागू करने के पहले छात्रों, शिक्षकों, शिक्षाविदों से सुझाव आमंत्रित किये जाते तो यह प्रणाली अव्यावहारिक नहीं होती। इससे पूर्व संगठन के प्रदेश मंत्री श्री हितेश शुक्ला ने कहा कि बाजारवाद, पूंजीवाद तथा वैश्वीकरण के कारण बेरोजगारी एवं रोजगार दोनों बढ़े हैं। चुनौतियों से निपटने एवं सामना करने का एकमात्र हथियार शिक्षा है। प्रतियोगिता के युग में कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण ही सेमेस्टर प्रणाली की शुरूआत की गयी लेकिन अफसरशाही की जिद एवं निर्णय थोपने की आदत ने इस प्रणाली पर प्रश्नचिन्ह खड़े कर दिये हैं। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए शिक्षाविद श्री बी. पी. मिश्रा ने कहा कि सेमेस्टर प्रणाली वास्तव में परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन है, शिक्षा व्यवस्था में नहीं। इस प्रणाली में उत्तर पुस्तिका देखने का अधिकार है। हमें इसे व्यावहारिक तौर पर लागू करना होगा। यह प्रक्रिया पारदर्शी एवं क्रमबद्ध होनी चाहिए। इस अवसर पर प्रदेश भर से आये छात्र–छात्राओं एवं शिक्षकों ने अपने सुझाव दिये।

अभाविप का प्रांतीय प्रबंधन उत्सव–चेतना २००९

गत 20,21,22 फरवरी को उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से राज्य के 120 कालेजों के 450 प्रबंधन छात्रों का एक राज्य स्तरीय प्रबंधन उत्सव 'चेतना 2009' के नाम से आयोजित किया गया। इस अवसर पर अनेक विषयों पर चर्चा सत्र हुए और प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं। चर्चा सत्रों को जाने–माने प्रबंधन विशेषज्ञों ने सम्बोधित किया जिसमें प्रमुख थे–प्रो.जयंत कुलकर्णी, श्री साईं प्रसाद, प्रो.तिरुपति राव। स्वदेशी के राज्य संयोजक श्री साईं प्रसाद ने वैश्विक आर्थिक मंदी पर बोलते हुए सावधान किया कि भारत को असीमित उपभोक्तावाद फैलाने वाली पश्चिमी सोच की नकल नहीं करनी चाहिए। अमरीका में तो हर घर में एक दर्जन से अधिक क्रेडिट कार्ड होते हैं जिसकी वजह से बचत से बढ़कर खर्च किया जाता है। इस कारण उनके ऊपर अरबों डालर का बकाया है। अमरीका का नागरिक अपने क्रेडिट कार्ड और पैन कार्ड पर आश्रित होकर रह गया है।

चैतन्य भारती इंस्टीटयूट आफ तकनालॉजी के प्रो.जयंत कुलकर्णी ने छात्रों से स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रबंधन के छात्र हमारे ग्रामीण जन से बहुत कुछ सीख सकते हैं जो अपने खेत और घर को इतनी अच्छी तरह से संचालित करते हैं कि इससे न केवल हमारी संस्कृति बल्कि अर्थव्यवस्था को भी बल मिलता है। आयोजन के अंतिम दिन उस्मानिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.तिरुपति राव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अपने संबोधन में उन्होंने राज्य भर के प्रबंधन के छात्रों को एक मंच पर लाने का प्रयास करने के लिए अभाविप को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत में पश्चिम के मुकाबले बचत को लेकर जागरूकता अधिक है। इस बचत के आधार पर अपनी विकास दर बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। हमारे वेदों की परंपरा में भारतीय अर्थ तंत्र के मौलिक सूत्र समाहित हैं और चीन के मुकाबले हम अपने बनाए अर्थ तंत्र पर मजबूती से खड़े हैं। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और भारतीय लोक और परंपरागत कलाओं का प्रदर्शन भी किया गया। कुलपति ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी दिए।

जरूरी है छद्म-सेक्युलरवादियों से बच कर रहना

– राम प्रसाद त्रिपाठी –

चुनाव का मौसम आता है और हमारे वामपंथी बुद्धिजीवी, कांग्रेसी पाखण्डी और पंच सितारा होटलों में रहने वाले लोग तथाकथित समाजसेवी सेक्युलरिज्म पर अपना ज्ञान बघारने में लग जाते है और इस मुद्दे पर हंगामा खड़ा करना शुरू कर देते हैं। उन्हें तो इतना भी मालूम नहीं है कि 'सेक्युलरिज्म' शब्द की अवधारणा भारत में कोई नई नहीं है, परन्तु भले ही इसके आंतरिक शब्दों का अर्थ अलग हो। भारत में सेक्युलरिज्म का उपदेश देना मूर्खता है क्योंकि इसकी अवधारणा तो भारत की मिट्टी में चिरन्तन काल से चली आ रही है। सच तो यह है कि हमारे तथाकथित सेक्युलर ब्रिगेड के लोग जिस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं, वह तो एक काल्पनिक बहुसंख्यक – अल्पसंख्यकों के बीच दीवार खड़ी कर छद्म–सेक्युलरिज्म का प्रचार कर रहे है जिससे कभी भी इस देश के लोगों में राष्ट्र के प्रति देशप्रेम की भावना का निर्माण नहीं हो सकता है।

यह दिखलाने के लिए कि वे ही सच्चे सेक्युलर सिद्धांतवादी है और अपनी सेक्युलर–विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए उन्हें बहुसंख्यकों की भर्त्सना करने में भी संकोच नहीं होता है। इस प्रकार की विचारधारा रखने से लोगों को एकजुट करने की बजाए होता यह है कि समस्या निरंतर बढ़ती चली जाती है। राष्ट्रीय एकता पनप तो नहीं पाती बल्कि अन्दरूनी रूप से लोगों में मजहबी उन्माद पैदा हो जाता है। समस्या निरंतर बनी रहती है जिससे राष्ट्रीय एकता की कीमत पर अल्पसंख्यक एकता को महत्व दिया जाता है, ताकि वोटबैंक की राजनीति चलती रहे।

काश, इस प्रकार का सेक्युलरिज्म ही राष्ट्रीय एकता निर्माण का ही सामंजस्यपूर्ण शक्ति बन पाता तो फिर कम्युनिस्ट शासित रूस और यूगोस्लोवाकिया क्यों विखण्डित होते। इस प्रकार का सेक्युलरिज्म सच्चे राष्ट्रवाद और देशभक्ति के विरूद्ध रहता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए केवल एक ही पहचान की बजाए अनेक पहचान की बात की जाती है चाहे वह साम्प्रदायिक पहचान के रूप में किसी भी समुदाय की क्यों न हो? अब आप ही बताइए, कौन सी विचारधारा विभाजनकारी है? जब एक ही पहचान का सवाल सामने आता है तो भारत विश्व के सभी देशों में एक ही बात के लिए विख्यात है और वह है भारत की प्राचीन सभ्यता की पहचान, जिसमें उसका उज्ज्वल इतिहास और संस्कृति भी शामिल रहती है। भला कौन भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने की बात सोच भी सकता है और फिर क्या

कोई कह सकता है कि ऐसा सवाल खड़ा कर वह सेक्युलरिज्म को आगे बढ़ा रहा है? क्या कोई व्यक्ति विभिन्न धर्मों के लिए अलग–अलग सिविल संहिताओं की बात कहे और फिर भी कहे कि वे ही सेक्युलरिज्म के हितों के चैम्पियन हैं?

पहले की तरह ही इस बार 2009 की चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही, साम्प्रदायिकता और सेक्युलरिज्म के बीच बहस फिर से सामने आ गई है। इस बार जिन व्यक्तियों ने इस बहस की शुरूआत की है, वह और कोई नहीं, वे हैं 'ग्रेट कामरेड' श्री प्रकाश करात और उनके साथीगण तथा कुछ पुराने कांग्रेस के बोगस–सेक्युलर मित्र। बार–बार उनकी एक ही रट लगी रहती है कि साम्प्रदायिक ताकतों को सत्ता में आने से रोकने के लिए केन्द्र में सेक्युलर पार्टियां मिलकर सेक्युलर सरकार बनाएंगी। परन्तु आम आदमी के लिए यह समझ पाना मुश्किल है कि कामरेडों का साम्प्रदायिकवाद और सेक्युलरवाद का मतलब क्या है? बल्कि यह बात और भी रोचक लगने लगती है कि भारत में वामपंथी प्रमाणपत्र देने वाली एजेंसी बन गई है कि कौन सेक्युलर है और कौन साम्प्रदायिक! उनके अनुसार–

♦अफजल गुरू, कसाब और मदानी जैसे आतंकवादियों के प्रति उदासीनता बरती जाए तब तो ऐसे लोग भी सेक्युलरवादी होते है परन्तु एमसी शर्मा के बलिदान का समर्थन किया जाए तो वे लोग साम्प्रदायिक बन जाते है।

♦एम.एफ. हुसैन सेक्युलर है परन्तु तस्लीमा नसरीन साम्प्रदायिक है, तभी तो उसे पश्चिम बंगाल के सेक्युलर राज्य से बाहर निकाल दिया गया।

♦इस्लाम का अपमान करने वाला डेनिश कार्टूनिस्ट तो साम्प्रदायिक है परन्तु हिन्दुत्व का अपमान करने वाले करूणानिधि को सेक्युलर माना जाता है।

♦मेजर संदीप उन्नीकश्ष्णन के बलिदान का उपहास उड़ाना सेक्युलरवादी होता है, हेमन्त करकरे के बलिदान पर प्रश्नचिह्न लगाने वाला सेक्युलवादी होता है, दिल्ली पुलिस की मंषा पर सवाल खड़ा करना सेक्युलरवादी होता है, परन्तु एटीएस के स्टाइल पर सवाल खड़ा करना साम्प्रदायिकता के घेरे में आता है।

♦राष्ट्र–विरोधी 'सिमी' सेक्युलर है तो राष्ट्रवादी रा.स्व.सं साम्प्रदायिक है।

♦एमआईएम, पीडीपी, एयूडीएफ और आईयूएमएल जैसी विशुद्ध मजहब–आधारित पार्टियां सेक्युलर है, परन्तु भाजपा साम्प्रदायिक है।

♦बांग्लादेशी आप्रवासियों, विशेष रूप से मुस्लिमों का और एयूडीएफ का समर्थन करना सेक्युलर है, परन्तु कश्मीरी पंडितों का समर्थन करना साम्प्रदायिक है।

♦नंदीग्राम में 2000 एकड़ क्षेत्र में किसानों पर गोलियों की बरसात करना सेक्युलरिज्म है परन्तु अमरनाथ में 100 एकड़ की भूमि की मांग करना साम्प्रदायिक है।

♦मजहबी धर्मांतरण सेक्युलर है तो उनका पुनः धर्मांतरण करना साम्प्रदायिक होता है।

♦कुछ चुनिंदा समुदायों को स्कालरशिप और आरक्षण सेक्युलरिज्म है परन्तु सभी योग्य–सुपात्र भारतीयों के बारे में इस प्रकार की चर्चा करना भी साम्प्रदायिक होता है।

♦मजहबी आधार पर आर्मी, न्यायपालिका, पुलिस में जनगणना कराना कांग्रेस और वामपंथियों की नजरों में सेक्युलरिज्म है परन्तु एक–भारत की बात करना भी साम्प्रदायिक है।

♦हिन्दू समुदाय के कल्याण की बात करना साम्प्रदायिक है तो उधर मुस्लिम तुष्टिकरण सेक्युलर है।

♦कामरेडों का नमाज में भाग लेना, हज जाना और चर्च जाना तो सेक्युलरिज्म है परन्तु हिन्दूओं का मंदिरों में जाना या पूजा में भाग लेना साम्प्रदायिक है।

♦पाठ्य–पुस्तकों में छत्रपति शिवाजी और गुरू गोविन्द सिंह जैसी धार्मिक नेताओं के प्रति अपशब्दावली का इस्तेमाल 'डिटोक्सीफिकेशन' या सेक्युलरिज्म माना जाता है और भारत सभ्यता का महिमामंडन साम्प्रदायिक कहा जाता है।

हमारे प्रिय छद्म–सेक्युलर कामरेडों, आखिर आप आम आदमी को क्या समझते हैं? क्या वे एकदम मूर्ख है? नहीं, बिल्कुल नहीं! वे आपकी मंशा और विदेशों के प्रति आपके नर्म रूख को वे भली भांति जानते हैं, वे आपकी गली–सड़ी विचारधारा को समझते हैं, जिसे पूरी दुनिया ने कूड़े में फेंक दिया है। आपने एक बार नहीं, दो बार नहीं,

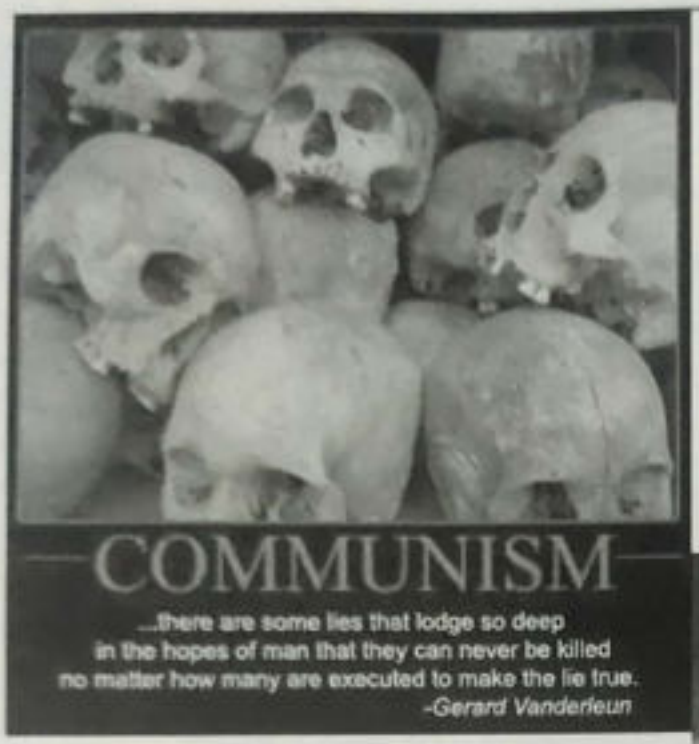

बल्कि कई बार अपने को राष्ट्र–विरोधी और समाज–विरोधी प्रमाणित कर दिया है।

आप तो उस विचारधारा के प्रवर्तक रहे हैं जिसने 1942 में 'भारत छोड़ो' आंदोलन का जबरदस्त विरोध किया, 1962 में आपने चीन–भारत युद्ध में भारत का विरोध किया, पाकिस्तान के साथ 1965 और 1971 के युद्धों मे भारत का विरोध किया, करगिल युद्ध में आक्रमणकारियों के समर्थन में आकर भारत की कार्रवाई पर सवालिया निशान लगाया, जब 1975 में राष्ट्रीय इमर्जेंसी लगी तो आपने लोकतंत्र का गला घोंटने का समर्थन किया, आपने अवैध बांग्लादेशी आप्रवासियों के देश–निश्कासन का विरोध किया, 'भारत के परमाणु शक्ति बन जाने' तक का विरोध किया, बल्कि आपने इस पर उस समय चीन का समर्थन किया जब वह परमाणु शस्त्रों का परीक्षण कर रहा था। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का विरोध किया। भारत में विकास और औद्योगीकरण का विरोध किया और आपकी पार्टी की शासित राज्य सरकार ने 'सेज' निर्माण के लिए निर्दोष किसानों पर गोलियों की बौछार की। आप तो वह लोग हैं जिन्होंने 'सोनार बागला' (पश्चिम बंगाल) को तबाह करके रख दिया। आपने अपने 30 वर्ष के शासन में राज्य को भारतीय राज्यों में सबसे निचले स्तर पर लाकर खड़ा कर किया है, पश्चिम बंगाल और केरल में सभी विकास–कार्य ठप्प हो गए हैं, आपने अपने स्वार्थ के लिए पूरी अर्थव्यवस्था और समाज को तबाह करके रख दिया है।

आप तो उसी वामपंथी मोर्चे के लोग हैं जिन्होंने अपने स्वार्थी राजनैतिक हितों के लिए यूपीए के बैनर तले साढ़े चार वर्षों तक कांग्रेस का खूब दोहन किया। और जब आपने देख लिया कि अब तो दूध मिलने वाला नहीं तो अपने उसे बाहर का दरवाजा दिखा दिया। कांग्रेसनीत यूपीए की तरह आप भी भारत और उसकी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं। आप भी उसी गठबंधन का हिस्सा थे जिसने देश को समृद्ध बनाने की बजाए गरीब बना कर रख दिया, किसानों के कल्याण की बजाए उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर किया, कीमतें स्थिर न रह कर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को आसमान तक पहुंचा दिया, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की बजाए तबाह कर दिया, आम आदमी की रोजी–रोटी को छीना, बेरोजगारी बढ़ी और उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ गई।

हमारे प्रिय कामरेडों, यह स है कि किसी भी व्यक्ति के लिए आपकी सही प्रकृति भांपना बेहद मुश्किल काम है परन्तु सीधे सादे शब्दों में यह तो कहा ही जा सकता है कि आप 'अवसरवादी' होने के अलावा कुछ भी नहीं रह गए हैं और आप सत्ता हथियाने के लिए किसी से भी हाथ मिला सकते हैं और हमारे इस महान देश को सीढ़ी दर सीढ़ी तबाह करने में जुटे हैं। वरना, उड़ीसा में जो बीजेडी दो महीने पहले साम्प्रदायिक थी, वह आपसे मिलने के बाद कैसे एक ही रात में सेक्युलर बन गई। यदि आप मानते हैं कि चन्द्रबाबू नायडू, जयललिता और देवगौड़ा साम्प्रदायिक थे, जब वे एनडीए के पार्टनर थे, तो अचानक वे आज कैसे सेक्युलर हो गए।

यह नितांत अवसरवादिता है और आप फिर से सेक्युलरिज्म के नाम पर सत्ता हथियाने की फिराक में लगे हैं। क्योंकि आम आदमी आपकी वास्तविक मंशा को समझने लगा है, इसलिए आप अपनी पार्टी के 80 वर्ष के इतिहास में अपने खेमे में 80 एमपी भी ला नहीं पाए। यदि राष्ट्र–विरोधी तत्वों के खिलाफ आवाज उठाना साम्प्रदायिक है, यदि अपने उज्ज्वल अतीत और संस्कृति पर अभिमान करना साम्प्रदायिक है तो इस महान देश का आम आदमी छद्म–सेक्युलर होने के बजाए स्वयं को साम्प्रदायिक कहलाना ही अधिक पसंद करेगा।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में शोध–छात्र हैं)

Whose elections were these anyway?

– Tarun Vijay –

The last phase of polling ended on May 13 and Lok Sabha election results will begin pouring in on May 16 morning. In between a world of words churned heavy doses of speculation and the nation was projected as waiting with utmost anxiety to know who would rule it in the next phase of governance. The media and political circles were seen decoding numbers, debating issues of great national importance like which party and conglomeration will align with whom at what cost. "Four singles" were projected as holding keys to make dreams of two "mixed doubles" true. Words like horse trading, head counts, going for the highest bidders and deals were afloat, and very grim looking, stiff-faced thinkers and editors were on prime-time debates guiding the nation with their serious analyses.

Meanwhile, those who desired governorships, ambassadorial assignments or positions of OSDs to ministers showed up at the bungalows of the promising winners and assured them, "Sir, I have confirmed news from IB, you are winning and sahib will certainly become PM. Congratulations in advance, sir. Please do not forget me, sir, when you take oath."

Usual things in this part of the world. Corporate giants and their lackeys were present in full strength and promised all out support to their "horses" for the next round of government making — post May 16.

This was happening when almost 50% of the Indian electorate chose not to vote.

And we shall be happy about the great vivacity, prudence and efficacy of our electorate and democratic institutions.

The second day, having returned from one such serious TV discussion on a very honestly fudged exit poll, we completed the ritual of watching Balika Vadhu at home and went out for "chaat" in Fateh Puri.

And while savouring the best mix of bhalla-papadi, I couldn't resist asking the "chaatwalla": "Kya khayal hai bhaiyya, kiski sarkar banegi (Dear brother, who you think will form the government)?"

He replied taking my serious query as a funny, unimportant one: "How does it matter to us? It matters to only those handful of people who know the leaders and are in their closer circles. Let any one form the government."

I dismissed it as a cynical answer of a semi-literate person who didn't realize the importance of his vote. The government he chooses decides the destiny of the country. Those who people parliament are called lawmakers and law is the vehicle that drives the national life.

Who was right — the "chaatwalla" or I?

I think the "chaatwalla" was right.

Where are the voter and the nation and the interest of the disadvantaged and the distanced people of this land in the decisions that party leaders are about to make to form the next central government?

Which party or front has put up a condition to introduce the universally available health scheme, an assured health insurance to all and better public hospitals as a precondition to form a coalition? Or which leader has announced that his support is assured to the party that promises good primary schools in his area, with the best of facilities available to the children of Shah Rukh and Ambani made available to the poor and farmers? Why can't we give top priority to our common, often voiceless, citizens? Just forget the individual election manifestos released by the parties. Everything depends on the common minimum programme that will be agreed upon by winning coalitions post May 16.

These were the elections that were contested by the rich to get richer at the expense of the poor and powerless, unorganized millions. Nowhere the issues of empowering the poor and low-income groups, or earmarking housing as a fundamental right and increased facilities and ultramodern training to the police and security forces were considered a winnable election slogan or a charter to earn people's mandate. How did the parties connect or even tried to befriend and educate a rickshaw puller on issues that affect his life as a citizen? Did they feel the need for it? He would be required only in a rally of the poor to be addressed by a rich leader. He is the class, which is made to get worked up on emotive issues and used as cannon fodder. He dies in greatly publicized agitations unsung with none of the red-eyed, angry leaders who led him to death caring how his family is continuing with a life that it didn't choose. Issues of Hindu-Muslim, caste and provincialism are raised just for the limited gains of vote and then easily forgotten once the space in Lutyen's Delhi is assured.

The life of a hawker or labourer who gets his daily wages after a cut by h[is] middleman contractor and the factory worker hasn't changed since last decade. Still in the remote villages water scarcity, famines, floods, 12-hour power cuts, bad roads and overloaded means of transportation are facts of life. The mushrooming growth of the new educational malls providing half-baked degrees to the aspiring youth and the huge number of increasing urban and rural unemployed semi-skilled work force can't get on to the agendas of any politician unless they form a usable vote bank. The urban public amenities, buses, railway stations and localities of the low-income group working people show unbelievable depths of human misery, filth, anarchical systemic failure and life in a subhuman condition.

The biggest fraud of our times has been to showcase improvement in the railways. You have to travel sleeper class to see the coaches filled with passengers like animals in a goods train with lower levels of cleanliness. Every major platform is choked with passengers squatting on the floors,

as there is no proper space for the travelers to wait and board the train with dignity. The politicians do not find it necessary to look at the common citizen with respect and provide him facilities he deserves by virtue of being an Indian citizen.

A senior member of the Indian Administrative Service, Alok Kumar, in a brilliant analysis, in Garhwal Post , has reflected on how these elections might have become less relevant for the millions of people who have restricted sources of income and are living on the edge: "At 267 million [2005] , the number of poor remains unacceptably large. If you also include the fact that of the remaining population, 190 million earn between $1 and $1.25 a day and a further 170 million earn between $1.25 and $1.35 a day, it would be clear that a large number of people, 55% to be precise, cannot afford a life of dignity. The increase in per capita income (currently $575) largely reflects the income growths of the top quintile of the population. It has been estimated by the Forbes 2006 list of study that the 32 Indian billionaires have amassed assets totaling $153.7 billion, equivalent to 15.4% of the GDP of the country and at a modest rate of return of 10%, they command close to 1.5% of the national wealth of the country. It could arguably be said that a few billionaires could possibly raise the mean income; without affecting the vast majority of poor.

"The symbiotic relationship between politics & big business has worried commentators enough to contemplate upon the possibility of an oligarchic state in India. Where does this leave the "Aam Admi? — the so called median voter? The farm loan waiver has been said to benefit the rich farmers more than the small and marginal ones, because the latter category was largely excluded from access to credit from government financial institutions and therefore relied more on private sources of credit. Schemes such as NREGP, RKVY & NRHM have been designed to reach exactly the median voter — "Aam Admi" but in the absence of reforms in the delivery mechanism, it is not certain as to what proportion of intended benefits is reaching the median voter. The Second Administrative Reforms Commission has submitted 11 reports so far, but any change in the governance structure still remains a commitment unfulfilled. The recent return to power of incumbent governments in Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Delhi was seen as the citizens' vote for good governance. I wish I could characterize it so, but I am not so sanguine. In Rajasthan, with an excellent record of implementation of NREGA entailing huge transfers of money to the rural labour, this was not sufficient to ensure re-election to the incumbent government ... The moral of the story - with due apologies to John Allen Paulos: 'It's Mean to Ignore the Median'."

It's not just true about the daily needs of an "aam aadmi", who is not touched by the politically active class, but also about the middle-income groups that form the majority of the Indian people put together. In our daily lives, from a berth reservation in the railways to getting your child admitted to a good school and having a driving licence to benefiting from the farmers' loan waiver scheme and getting a medical aid you need a political contact. Netaji's letter and his phone calls are too important for small mercies. Each neta, on an average is a controller of a few hundred crore rupees and lives a luxurious life in his green acres maintained at public money. Syama Prasad Mookerjee, a great academic and nationalist ideologue said, "No government which calls itself civilized has the right to exist unless it can so formulate and administer its policy as to keep the people under its charge free from minimum want and privation." But who cares?

The debates you see on the TV screens by intelligent people are not meant for the poor and the median. ■

Vinayak Damodar Savarkar : A Great Freedom Fighter

Vinayak Damodar Savarkar was born on May 28, 1883 in the village of Bhagpur near Nasik. Vinayak was one of four children. When Vinayak was nine years old, his mother died of cholera. Damodarpant himself looked after his children thereafter. Vinayak's father died of plague in 1899.

Vinayak's patriotic spirit found an outlet through an organization called the Mitra Mela that he formed. Vinayak inducted young patriotic men like himself into the Mela. He encouraged the members of the Mela to strive for "absolute political independence for India" by whatever means necessary. In March 1901, Vinayak was married to Yamunabai. After his matriculation examination, Vinayak enrolled in the Fergusson College in Punea in 1902.

Savarkar very soon dominated campus life. He, along with a group of students began dressing alike and using swadeshi goods only. He renamed the "Mitra Mela" as "Abhinav Bharat" and declared that "India must be independent; India must be united; India must be a republic; India must have a common language and common script.".

Vinayak left for London to study law in June 1906 on receiving a scholarship. In London, Savarkar founded the Free India Society which held weekly meetings and celebrated Indian festivals and anniversaries of important figures and days in the Indian freedom struggle. In 1908, Savarkar completed "the History of the War of Indian Independence." The text was banned by the British even before it was published for being "revolutionary, explosive and seditious."

Savarkar was implicated in the murder of Mr. Jackson because of his contacts with the India House. Savarkar moved to Madame Cama's residence in Paris. A warrant was issued and Savarkar was arrested on March 13, 1910. In his last letters to a close friend, he conveyed his plan to attempt to escape from custody at Marseilles. His friend was to be waiting there with a car. The escape attempt at Marseilles failed. The car arrived too late. Savarkar was brought to Bombay on the S.S. Morea and detained at Yeravada jail. Savarkar was tried and found guilty on the counts of "waging war by instigation using printed matter, and providing arms... (and) for abetting the murder of Mr. Jackson (p.118, Berry)." Savarkar was awarded 25 years imprisonment on the former charge and 25 years for the latter. A sum total of 50 years imprisonment which he was to serve at the Andamans prison. "Veer" Savarkar was only 27 years old at the time of his sentencing!

Savarkar arrived at the Andamans prison on July 4, 1911. On May 2, 1921, the Savarkar brothers were brought back to India .Savarkar remained imprisoned in Ratnagiri Jail and then in Yeravada Jail until January 6, 1924 when he was freed under the condition that he would not leave Ratnagiri district and abstain from political activity for the next five years. At the end of his five year confinement in Ratnagiri, Savarkar joined Tilak's Swaraj Party and founded the Hindu Mahasabha.

When the Indian Army entered Lahore, Savarkar rejoiced saying that the "best way to win a war was to carry it into the enemy's land "Veer" Savarkar died on February 27, 1966.

नई सरकार के समक्ष चुनौतियां

अरूण कुमार

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में 15 वीं लोकसभा के चुनाव हो रहे और आज आजादी के 61 वर्षों के बाद भी देश के सामने समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। रोटी, कपड़ा और मकान से बढ़कर अब समस्याओं का दायरा सुरक्षा के सवाल के तौर पर सामने आ रहा है। देश में आतंकवाद की निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस बीच सभी राजनीतिक दलों को पूर्ण रूप सुरक्षा मुहैया कराने की बात कर रही हैं, लेकिन वायदों से आगे जाकर नई सरकार को इस दिशा में मजबूती से कदम उठाने पड़ेंगे। भारत के पड़ोसी देशों में अस्थिरता एवं अशांति का माहौल है, जिसका असर हमारे देश पर पड़ सकता है। इस पर भी ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत है। विदेशी बैंकों में छिपे काले धन को वापस लाने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि इससे बहुत सी समस्याएं हल हो सकेंगी। मंदी के दौर में जहां नौकरियां घट रही हैं, वहां नए रोजगार उत्पन्न करने भी सरकार की राह आसान नहीं होगी। एसोचैम की नई रिपोर्ट को देखें तो भारत में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिनके पास सिर ढकने को छत नहीं है। जिसके लिए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सरकार को पौने पांच करोड़ घरों की व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ-साथ किसानों के लिए सरकार के सामने कई चनौतियां हैं। एक ओर सरकार दिखाती है कि हमारा उत्पादन दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हमें खाद्य पद्धार्थ बाहर से आयात करने पड़ते हैं। देश में सूखा, बाढ़ और अकाल जैसी स्थिति से निपटने के कारगर उपाय भी करने होंगे। दुनिया में मंदी के चलते आई बेरोजगारी को भारत से कम करने के लिए सरकार को पिछली सरकार की बंद कर दी गई परियोजनाओं को आगे बढ़ाना होगा।

आशुतोष शुक्ला

भारत जैसे बहुसांस्कृतिक एवं विकासशील देश में समस्याए भी बहुत हैं, जिनसे आने वाली सरकार को रूबरू होना पड़ेगा। चाहे सरकार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बने या लालकृष्ण आडवाणी की अगुवाई में। आर्थिक मंदी से भारत भी बच नहीं पाया है। यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में इससे निपटने का प्रयास किया, लेकिन समस्या फलक को देखते हुए इससे निपटने में अभी समय लगेगा। आने वाली सरकार के लिए मंदी से पार पाना एक बड़ी चुनौति होगी। साथ ही यह देखना भी दिलचस्प होगा कि वह किस प्रकार मंदी के कारण बेरोजगार हुए लोगों को प्रतियोगितावादी बाजार में दोबारा स्थापित कर पाती है।

आंतरिक सुरक्षा भी आगामी सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौति होगी। आगामी सरकार को सभी प्रदेशों की आम सहमती हासिल कर एक ऐसी नीति का निर्माण करना होगा, जिससे कि आतंक से सख्ती से निपटा जा सके। श्रीलंका में एलटीटी व सरकार के बीच संघर्ष के कारण तमिलों के विस्थापितिकरण की समस्या व उनके अधिकारों की रक्षा, साथ ही चीन के साथ श्रीलंका सरकार की बढ़ती नजदीकियां भी आगामी सरकार की चिंता का विषय होंगी। कॉमनवेल्थ खेलों का शांतिपूर्ण आयोजन, क्षेत्रवाद की समस्या, स्विस बैंक में जमा काला धन भारत लाना एवं समस्त भारत के लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना आगामी सरकार के समक्ष किसी चुनौती से कम नहीं है।

दिनेश

हरित क्रांति की शुरुआत हुए 40 सालों से ज्यादा समय बीत चुका है। हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले पांच नदियों का प्रदेश पंजाब अब बेआब हो है। खेती की जमीने अत्यधिक रसायनों के उपयोग से बांझ होने लगी है। भूजल स्तर अत्यत नीचे चला गया है, जो बचा भी वह आर्सेनिक से प्रभावित है। दूसरी ओर हम मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर इस भ्रम में रहे कि पंजाब का किसान समृद्धि के सोपान तय कर रहा है। मारूति में बैठे हुए किसानों को देखना तो आम बात माना जाता था। लेकिन अब वही पंजाब किसानों की आत्महत्याओं का गवाह बन रहा है। मिट्टी के जहरीली हो जाने के कारण

लोग कैंसर से मर रहे हैं। यह एक हरित क्रांति की देन कही जा सकती है। हाल ही में यूपीए सरकार ने दूसरी हरित क्रांति की घोषणा न जाने किस आधार पर कर दी, बात समझ से परे है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के हाल के अध्ययन बताते हैं कि पंजाब के 89 फीसदी किसान कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। ये आंकड़े खतरनाक संकेत कर रहे हैं। कहीं पंजाब दूसरा विदर्भ या फिर बुंदेलखंड तो बनने नहीं जा रहा है? इस बात पर गौर करने की जरूरत है।

2005 में कृषि शोध, शिक्षा एवं व्यापार के लिए केआईए समझौता भारत ने अमेरिका के साथ किया है। जानकारों का मानना है कि इस समझौते से सरकार ने मोन्सेन्टो एवं वालमार्ट जैसी कंपनियों के लिए सरकार ने दरवाजे खोलनी की तैयारी सरकार ने कर ली है। इस तरह से खेती से किसानों को बेदखल करने की तैयारी की जा रही है। यह नहीं भूलना चाहिए कि देश की करीब 70 फीसदी आबादी खेती पर ही निर्भर करती है। कहां जाएंगें वे किसान? इस बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा। कोई भी सरकार आखिर देश की इतनी बड़ी आबादी के हितों की उपेक्षा कैसे की जा सकती है।

पंकज

गहराता हुआ जल संकट एक चिंता का विषय है। जिस तरह से नदियों का जल सूख रहा है और उसमें प्रदूषण निरंतर बढ़ रहा है, उससे आने वाले समय के लिए खतरा बढता जा रहा है। आखिर हम आने वाली पीढ़ियों को कैसा भारत सौंपेंगे? यह सोचना होगा। क्या आतंक एवं प्राकृतिक संपदा से हीन भारत हम उन्हें देने जा रहे हैं। यह प्रश्न महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसके अलावा शिक्षा का निजीकरण एक महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए। इसके कारण गरीब छात्रों की उच्च शिक्षा से दूरी बढ़ती जा रही है। जबकि मदरसों को सहूलियतें देकर सरकार मुस्लिम तुष्टिकरण में जुटी हुई है। यह विडंबनापर्ण है। सबको समान एवं अनिवार्य शिक्षा सुलभ हो सके इसकी व्यवस्था करनी होगी। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल रोजगार से जुड़ा है। रोजगार के अवसर सृजन करना एवं रोजगारपरक शिक्षा समाज के सभी तबकों को उपलब्ध कराना सरकार के एजेंडे में मुख्य तौर पर होना चाहिए। ■

NGOs, Teesta spiced up Gujarat riot incidents: SIT

The Special Investigation Team for Gujarat riots has severely censured NGOs and social activist Teesta Setalvad who campaigned for the riot victims.

In a significant development, the SIT led by former CBI director R K Raghavan told the Supreme Court that the rights activist cooked up macabre tales of wanton killings.

Many incidents of killings and violence were cooked up, false charges were levelled against then police chief P C Pandey and false witnesses were tutored to give evidence about imaginary incidents, the SIT said.

22 witnesses, who had submitted identical affidavits before various courts relating to riot incidents, were questioned by the SIT which found that they had been tutored and handed over the affidavits by Setalvad and that they had not actually witnessed the riot incidents.

The SIT also found no truth in the following incidents widely publicised by the NGOs:

* A pregnant Muslim woman Kausar Banu was gangraped by a mob, who then gouged out the foetus with sharp weapons
* Dumping of dead bodies into a well by rioteers at Naroda Patiya
* Police botching up investigation into the killing of British nationals, who were on a visit to Gujarat and unfortunately got caught in the riots

On a reading of the report, it is clear that horrendous allegations made by the NGOs were false. Stereotyped affidavits were supplied by a social activist and the allegations made in them were found untrue."

प्रीति पाण्डेय

आज जहां व्यंग्य लेखन की मांग बाजार का स्वरूप देखते हुए दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है उसी तरह उस लेखन को पूरा करने के लिए बाजार में व्यंग्य चित्रकारों की मांग जोरो पर है। गम्भीर विषयों को रोचक ढंग से अपनी चित्रकारी के माध्यम से पाठकों तक संदेश देने का नाम एक व्यंग्य चित्रकार का होता है। यदि यह कहा जाए कि लेखन को समझने की समझ होने पर ही चुंकि वह चित्रकारी करता है इसलिए वह एक चित्रकार के साथ–साथ एक पत्रकार भी होता है जिसकी नजर बड़ी पैनी होती है जो चीजे किस अंदाज में हो रही है और उन्हें पाठकों के सामने किस तरह परोसना है बखूबी जानता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे बन सकते हैं आप एक व्यंग्य चित्रकार?

व्यंग्य चित्रकारी में बनाएं भविष्य

गम्भीर चीजो को सीधे–सीधे कहना थोड़ा मुश्किल होता है और यदि कह भी दिया जाए तो वह मुद्दा कई बार और ज्यादा गम्भीर हो जाता है जिससे पाठको तक वह संदेश नहीं पहुंच पाता जो कि एक लेखक अपने लेखन के जरिए पहुंचाना चाहता है। लेकिन जब काटूनिंग कला के माध्यम से उस लेखन की बात को सामने रखा जाता है तो समाज में वह संदेश एक बच्चा भी समझ पाता है और समाज की बात समाज तक आसानी से पहुंच जाती है। यह बात केवल प्रिंट मीडिया की ही नहीं है बल्कि इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इस तरह की कार्टूनिंग कला का विशेष महत्व है और जिसका एक अलग ही प्रभाव दर्शकों पर पहुंचता है। चूंकि यह मीडिया का वो हिस्सा होता है जो मीडिया के मिशन को बरकरार रखते हुए उसे उबाउ नहीं होने देता। संदेश को इस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है जिससे पाठक या दर्शक बोर भी न हो और संदेश का असर भी उनके दिलो–दिमाग पर रहें। बड़ी से बड़ी बात को अपने एक छोटे से चित्र के द्वारा कहने सच में एक बहुत बड़ी कला है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें ये कला बचपन से ही होती है जिसे पहले के माता–पिता पागलपन कहा करते थे आज वही पागलपन रोजगार का स्वरूप बन चुका है। गुस्ताखी माफ, पोल खोल का बन्दर अपनी बातों में ऐसी–ऐसी बात कह जाता है जो कि यदि सामान्य तौर पर कही जाए तो न जाने क्या से क्या हो जाए लेकिन चूंकि वहा बात एक कार्टून ने कही है तो उस बात को ज्यादा तूल नहीं दिया जाता और समाज के बीच में वो बात भी पहुंच जाती है। बस यही सबसे बड़ी खूबी है इस कला की।

योग्यताएं

102 परीक्षा के बाद कार्टूनिंग को कैरियर के रूप में चुना जा सकता है, इसके बाद ही इसकी पढ़ाई किया जा सकता है।

अतिरिक्त योग्यता

इस पाठ्क्रम को पढ़ने के साथ–साथ यदि छात्र मल्टी मीडिया का कोर्स कर लेता है तो उसके लिए काटूर्निंग का कोर्स सिखना काफी सरल हो जाता है। चूंकि इससे छात्र को तकनीकी पहलुओं को समझने में सहायता मिलती है और वह अलग–अलग तरह के सॉफ्टवेयर पैकेज का इस्तेमाल करने का आदी हो जाता है।

साथ ही कार्टूनिग में भविष्य बनाने के लिए इस कोर्स को करना ही काफी नहीं होता बल्कि छात्र मे चित्र बनाने, कार्टूनिंग कला का अपना कर सामाजिक, राजनीतिक संकट एंव विपतियों को व्यक्त करने की प्रतिभा होनी चाहिए जो वह किसी संस्थान से नहीं प्राप्त कर सकता। वह अपनी प्रतिभा को संस्थान में और अच्छा बना सकता है लेकिन चित्र बनाना नहीं सीख सकता जब तक उसका इस क्षेत्र में रूचि ही न हो।

रोजगार की सम्भावनाएं

व्यंग्य चित्रकार में यकीनन रोजगार के काफी अच्छे विकल्प हैं। व्यंग्य चित्रकारी में दक्ष कोई भी व्यक्ति किसी

भी पब्लिशिंग हाउस में व्यंग्य चित्रकार के तौर पर नौकरी कर सकता है।

इलैक्ट्रानिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया आज दोनों ही मीडिया में व्यंग्य चित्रकार की काफी मांग है।

आप किसी विज्ञापन एजेंसी में भी नौकरी के लिए कोशिश कर सकते हैं।

लेकिन यह भी बात तय है कि कोई भी संस्थान आपको नौकरी तभी देगा जब आपमें व्यंग्य चित्रकारी करने की कला बहुत ही प्रभावित हो। इसके लिए आपकी कल्पना शक्ति का अच्छा होना बहुत जरूरी है।

संस्थानः –

शंकर अकादमी ऑफ आर्ट,बहादुर शाह जफर मार्ग नइ दिल्ली

सर जे.जे स्कूल ऑफ आर्ट, डॉ. डी.एन रोड, मुम्बई

नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ डिजाइन, पालदी, अहमदाबाद

द दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, तिलक मार्ग, नई दिल्ली

वेतनः–

कार्टूनिंग कला में महारत प्राप्त व्यक्ति के वेतन की शुरूआत 7000 से शुरू होती है लेकिन आपका वेतन इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किस कंपनी में है और कहां काम कर रहे हैं। बडी–बडी कम्पनियों में यह वेतन 15000 से 25000 हजार तक भी मिलता है।

साभार : सहारा

Pragyik Vidyarthi Parishad, Nepal, Demands Better Opportunities in Technical Education

Pragyik Vidyarthi Parishad, a premier student organisation of Nepal demanded better facilities for technical and vocational education for all students in Nepal. The Parishad also demanded that moral and cultural education, including the spirit of nationalism and patriotism, should form the part of all curriculums. The demands were made at a massive rally organised on March 27, 2009 in Kathmandu.

Represented by the students from almost all the districts of Nepal, the rally started at Siphal, near the Pashupatinath Temple, at 11 am and culminated in a mass gathering at Khulamanch, after passing through major parts of the city like Goushala, Old Baneshwor, Dilli Bazar, Putalisadak, Exhibition Road, and Siphal Gate.

Addressing the students Shri Sunil Ambekar, national organising secretary of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) congratulated the Nepalese students and youths for consciously raising voice for educational reforms and protection of democracy. National organising secretary of Pragyik Vidyarthi Parishad Shri Deepak Kumar Adhikari, general secretary Shri Narayan Prasad Dhakal, secretary Shri Keshav Raj Panthee and Central Executive Member Shri Mahesh Paudyal, Kathmandu secretary Shri Sushil Koirala, girls' leader Ms Bimala Giri also spoke on the occasion. A memorandum, demanding comprehensive educational reforms was submitted to the Prime Minister through Shri Janardan Sharma Prabhakar. The memorandum said, "Education should be placed out of the purview of General Agreement and Trade in Services (GATS) and educational framework should be capable of establishing Sanskrit Language as the fountain of all languages, and hence the need to promote and conserve it should be prioritised while allowing regional languages and dialects to flourish and prosper," the memorandum added.

Delhi

ABVP's New Campaign for Young Voters

Urging the students to exercise their right to vote, the Delhi unit of ABVP has launched a campaign called "My Vote My Voice". The campaign will cover the students of the Delhi University, the Jawaharlal Nehru University, the Jamia Millia Islamia, the Guru Gobind Singh Indraprastha University, the Indian Institute of Technology, Delhi, and other educational institutions in the Capital.

The ABVP has released different kind of posters and feedback forms on election issues that will be distributed among the students. The campaign will be carried out extensively for the next two weeks.

ABVP national executive member Vikas Dahiya, raised the issue of a large number of outstation students studying at the Delhi University who were unable to cast their vote because of the distance factor and ongoing annual exams. "We will soon submit a memorandum in this regard to Vice-Chancellor Deepak Pental and the Election Commission of India for making alternative arrangements for these students," he added.

Karnataka

Stop Commercialisation Of Professional Courses: ABVP

Udupi district unit of ABVP staged a dharna near the service bus-stand on May 8 in protest against the State Government's policy on high fees for professional courses and the CET seat matrix. Sri MS Damodar, organising secretary of district unit, said instead of providing social justice, the State Government gifted five per cent more seats to the management of professional colleges. He demanded that the commercialisation of professional courses should be stopped and the fees of the professional courses should not be beyond the reach of common man.

The protesters said the Government should have a major say in professional courses and it should formulate a comprehensive law to regulate admission to professional courses and its fees. A committee should be formed to deal with admission and fee structure for the professional courses. An education development bank should be set up to help the economically weak and talented students in pursuing professional courses. There should be a single common entrance test and single window clearance for professional courses. The activists also submitted a memorandum to Deputy Commissioner in this regard.

Kerala

No need for AMU centre in Malappuram: ABVP

The attempts to set up a campus of Aligarh Muslim University (AMU) at Malappuram in Kerala received strong opposition from the nationalist forces across the state. The Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) started an agitation in the form of a Vahana Pracharana Yatra in the Muslim-dominated district to expose the conspiracy behind the setting-up of the AMU centre in Malappuram.

ABVP national secretary N Ravikumar inaugurated the three-day Yatra on March 16 near the Calicut University premises. He criticised the Congress and the communists for the divide-and-rule policy. He said the mindset of the AMU is still pro-Pakistan. "Establishing five regional centres of the University is nothing but a plan to

vivisect the nation into many parts," he said. Criticising the double standard of the LDF government in Kerala, he said the government has no money to acquire land for its own state universities and colleges and it is now funding the AMU centre in the state. "While many state universities are struggling with financial crunch the state government is allocating crores of rupees for AMU campus. They are only looking at the bulk of votes that may come to their favour in the Lok Sabha polls in Muslim-dominated constituencies. Any move to communalise the education will be opposed tooth and nail," he added. ABVP state vice president V Unnikrishnan explained as to why the ABVP was opposing the AMU campus in the state.

Sri Ravikumar flagged off the Yatra by handing over the ABVP flag to district convenor K Printumon. The Yatra received huge reception at various places. Many ABVP leaders addressed the public meetings at Parappanangadi, Tanur, Tirur, Kuttipuram and Ponnani. On the second day, the Yatra received massive receptions at Valanchery, Kadampuzha, Kottakkal etc.

Nationwide Campaign by ABVP to Educate Young Voters

Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) is going to launch a countrywide campaign to educate the young voters. The campaign to be started in all the states from first week of April will be taken up on different dates in different states. According to Shri Vishnu Dutt Sharma, national general secretary of ABVP, preparations for the campaign have been made in all the states.

In a statement issued from Mumbai, he said about 65 per cent of the total population of the country is youth and about 45 per cent of them have voting right. He said the youth couldn't elect a capable government until they are aware of the real condition of the country. It is with the objective to educate the youth of the present condition the ABVP has taken the decision to launch the nationwide drive. It would appeal to the youth to think, consider the nation's betterment before voting for any candidate or political party. "We get the right to vote at the age of 18. During this drive, we will appeal to the youth to think over the various national issues before voting for any party," said Shri Sharma.

Shri Sharma pointed out that during the campaign the youth would be requested to elect only those leaders who would not compromise on nation's security at any cost, enact laws against those who give shelter to terrorism, expatriate the Bangladeshi infiltrators, hang Afzal to death, discard the proposals of Sachar committee, create new avenues of employment and education for youth, stop commercialisation of education, bring Indianisation in education, stop appeasement in education field, give first right to poor subjects on national resources and not to Muslims and respect the martyrs, heritage and culture of the nation.

ABVP has printed some pamphlets, posters, banners and stickers on the theme. Short messages would also be sent through mobiles and some corner and gate meetings would be organised to educate the youth.

Former Workers Get together - Bhopal

Blood Donation camp - Jammu

Dharna against missionary school - Kerala

युवा मतदाता जागरण अभियान

Campaign

Street Play